रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

गुरुवार
12 नवम्बर -2026
वर्ष 11, अंक 62
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची


पेज-8

25 बड़े प्रोजेक्ट में देरी, 2 लाख करोड़ खर्च बढ़ा

● इतने में 4200 स्कूल बनते, 1400 से ज्यादा अस्पताल ● केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की बड़ी परियोजनाओं में देरी अब सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 1,853 चालू परियोजनाओं की लागत 3.22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित 25 मेगा परियोजनाओं का बजट ही 2.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है।

यह कुल लागत-वृद्धि का करीब 65 फीसदी हिस्सा है। यह राशि इतनी बड़ी है कि इससे 50 करोड़ की लागत वाले 4,200 से अधिक स्कूल या 150 करोड़ रुपए वाले 1,400 से ज्यादा अस्पताल बनाए जा सकते थे। इससे



दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दो प्रोजेक्ट भी तैयार हो सकते थे।

कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन 30 साल पीछे- समय-सीमा के मामले में भी स्थिति चिंताजनक है। कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन इसमें सबसे ऊपर है। इसे मार्च 2005 तक पूरा करना था, लेकिन अब इसका लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है यानी परियोजना 25 साल पीछे चली गई है। इसके बाद सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी जलविद्युत परियोजनाएं हैं, जिनकी समय-सीमा में 16 साल से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह है कि जिन सुविधाओं का लाभ जनता को एक-दो दशक पहले ही मिल जाना चाहिए था, उनके लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि, 1,360 परियोजनाएं ऐसी भी हैं, जो समय पर या केवल दो साल तक के विस्तार के साथ चल रही हैं।

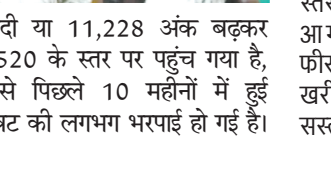
सरकार बदलने से प्राथमिकता बदलती है, फंड में देरी होती है

पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा के मुताबिक, कई बार लंबे प्रोजेक्ट के दौरान सरकार बदलने से जब नई सरकार की प्राथमिकता बदल जाती है तो फंड जारी होने में दिक्कतें भी आती हैं, उससे प्रोजेक्ट और डिले होते हैं लेकिन अब ऐसे उदाहरण चुनिंदा ही हैं। कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स प्रशासनिक और नीतिगत बाधाओं के कारण अटके हैं। अब देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दो चरणों में होते हैं। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण और वन मंजूरियां ली जाती हैं, जबकि दूसरे चरण में निर्माण कार्य शुरू होता है। 2013 के कानून से उचित मुआवजा मिलने के कारण विरोध कम हुआ है। टेंडर में प्रतिस्पर्धा के कारण कई प्रोजेक्ट्स तय बजट से 10-15 फीसदी कम लागत में बन रहे हैं। आने वाले समय में बहुस्तरीय निगरानी की वजह से देरी और लागत बढ़ने की समस्या तेजी से कम होगी।

असम में ट्रेन पटरी से उतरी, 50 पैसेंजर घायल

लोको पायलट बोले-सिग्नल रेड है, ब्रेक नहीं लग रहे

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के कामरूप में बुधवार सुबह करीब 6.54 बजे कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे में 50 पैसेंजर घायल हुए हैं। हालांकि रेलवे का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुताबिक, डिगारू स्टेशन पर ट्रेन को दूसरी लाइन पर लेने के दौरान लोको पायलट स्पीड कम नहीं कर सका, इससे ट्रेन डेड एंड पर लगे बैरिकेड्स से टकरा गई। 45 सेकेंड के वीडियो में इंजन के लोको पायलट केबिन का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसमें कंट्रोल पैनल, डिजिटल डिस्प्ले, स्विच और इंजन के उपकरण लगे हुए हैं। इसमें लोको पायलट कह रहे हैं- 'कुछ भी काम नहीं कर रहा। सिग्नल रेड हैं। इमरजेंसी लगा हुआ है, काम नहीं कर रहा है।



संक्षिप्त समाचार

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था

वाराणसी (एजेंसी)। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े पुराने प्रस्ताव का जिक्र किया है। उन्होंने इसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जोड़ते हुए आपातकाल के दौरान इसकी योजना बनाए जाने की बात लिखी है। किताब में लिखा- आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने काशी विश्वनाथ क्षेत्र के चौड़ीकरण और वहां सुधार का प्रस्ताव रखा था। विश्व के सबसे प्राचीन शहर में मकानों की भारी तोड़फोड़ और जनता के विरोध की आशंका को देखते हुए इंदिरा गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया था और उस काम को रुकवा दिया था।



बनारस रोड शो में बेहोश हुई थीं, कंधे में हुआ था फ्रैक्चर- सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अगस्त 2016 के वाराणसी दौरे के दौरान हुई घटना का भी जिक्र किया है। उस समय सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रोड शो से पहले सोनिया गांधी ने वाराणसी में चुनावी रैली की थी। किताब में लिखा है कि करीब पांच घंटे लंबे रोड शो के दौरान अत्यधिक थकान के कारण सोनिया गांधी बेहोश होकर गिर गई थीं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था। उनका कंधा बुरी तरह टूट गया था।

राजस्थान के वीर शासकों की गौरवगाथाओं पर बनेगी फिल्म 'शासक'

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान की धरती ने इतिहास में ऐसे कई वीर शासकों को जन्म दिया, जिनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल की गाथाएं आज भी देशभर में गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। अब राजस्थान के इसी गौरवशाली इतिहास को बड़े पर्दे पर जीवंत करने की तैयारी की जा रही है। निर्देशक नरेंद्र सिंह मीणा पहली बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फीचर फिल्म 'शासक' लेकर आ रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इसमें अभिनेता मुकेश चावंडिया मुख्य भूमिका में नजर



आएंगे। फिल्म को भव्य ऐतिहासिक ऐक्शन फिल्म के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए राजस्थान के वीर शासकों के संघर्ष, साहस और गौरवशाली विरासत को सिनेमाई अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। मेकर्स ने बताया कि फिल्म 'शासक' का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक घटनाओं को पर्दे पर दिखाना नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले वीर शासकों के व्यक्तित्व, उनके शासन, युद्ध कौशल और मातृभूमि के प्रति समर्पण को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। राजस्थान का इतिहास वीरता और बलिदान की अनेक कहानियों से भरा हुआ है। यहां के शासकों ने अपने राज्य, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए। फिल्म के जरिए इन्हीं ऐतिहासिक प्रसंगों और गौरवगाथाओं को दर्शकों के सामने लाने का प्रयास किया जाएगा।

रिटायर्ड अफसरों पर भी लागू होगी आचार संहिता

5 राज्यों में चुनाव से पहले चुनाव आयोग का फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत आचार संहिता सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि रिटायर होकर फिर से सरकार के लिए काम कर रहे अफसरों और लोगों पर भी लागू होगी। आयोग ने यह फैसला कुछ लोगों पर सरकारी पद के गलत इस्तेमाल की शिकायतों के बाद लिया। अब उन्हें राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी और चुनाव प्रचार या कैंपेनिंग से दूर रहना होगा। चुनाव आयोग ने इस फैसले को लेकर गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 9 नवंबर को लेटर भेजा है। आयोग ने चुनाव वाले क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने पर भी रोक लगाई है। **शिकायतों के बाद आयोग का फैसला-** एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले भी ऐसी शिकायतें मिली थीं। इनमें कहा गया था कि राज्य सरकारों से अलग-अलग भूमिकाओं में जुड़े रिटायर्ड अधिकारी चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों की बैठकें बुलाते हैं।



10 महीने में 16 फीसदी गिरा बाजार

महीने भर में रिकवरी

● सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 81,500 पर, निफ्टी में 100 अंक की तेजी

मुंबई (एजेंसी)। शेयर बाजार में सेंसेक्स बुधवार को 400 अंक चढ़कर 81,500 के पार पहुंच गया। यानी, इसमें 0.5 फीसदी की बढ़त है और इससे निवेशकों की दौलत 6 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। इधर, निफ्टी 100 अंक की तेजी के साथ 25,130 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसमें 0.34 फीसदी की तेजी है। आज बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त है। 1 जनवरी 2026 को सेंसेक्स 85,188 के स्तर पर था। इसके बाद बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और 1 अक्टूबर को सेंसेक्स 71,292 के इस साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस दौरान बाजार 16 फीसदी या 13,896 अंक टूटा। 1 अक्टूबर को 71,292 का निचला स्तर छूने के बाद बाजार में तेजी आई। बीते एक महीने में सेंसेक्स 15 फीसदी या 11,228 अंक बढ़कर 82,520 के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे पिछले 10 महीनों में हुई गिरावट की लगभग भरपाई हो गई है।



शेयर बाजार में तेजी की तीन बड़ी वजह

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट : अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, जिससे मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई रुकने या प्रभावित होने का डर कम हो गया है। इस खबर के बाद ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें घटकर दो महीने के निचले स्तर यानी 89.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं। भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने पर बिल घट सकता है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला

तीन जवान गंभीर रूप से घायल इलाके की सुरक्षा की गई सख्त



श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने सीआरपीएफ के अखरान कैंप में नाका ड्यूटी पर तैनात जवानों पर फायरिंग कर दी। घटना करीब 2.15 बजे की है। इसमें तीन जवान घायल हो गए।

उन्हें अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षाबल हमलावरों की तलाश में जुटे हैं। हालांकि किसी आतंकी संगठन ने तत्काल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हमला लश्कर ए तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले द रजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के आतंकी लतीफ बट के माडयूल ने किया है। जानकारी के अनुसार, कुलगाम के आखरन नौपुरा में बुधवार की दोपहर को आतंकियों ने सीआरपीएफ 46वीं वाहिनी के जवानों ने एक नाका लगाया हुआ था। नाका पार्टी वहां से गुजरने वाले वाहनों व लोगों की जांच पड़ताल कर रही थी। लगभग सवा दो बजे के करीब दो युवक नाके पास पहुंचे हमला कर दिया।

अब एनएसजी कमांडो की बदलेगी यूनिफॉर्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्लैक कैट कमांडो की मशहूर काली वर्दी अब बदलने जा रही है। वजह है- भयंकर गर्मी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) ने अपने वीआईपी सुरक्षा में लगे कमांडो के लिए नई ब्रीदेबल यानी सांस लेने वाली यूनिफॉर्म बनाने की सिफारिश की है। ये यूनिफॉर्म नायको कपड़े से बनेगी, जिसमें नायलॉन और कॉटन होता है। यह कपड़ा हवा और नमी को आसानी से बाहर निकलने देता है। अप्रैल में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात कमांडो करीब 44 डिग्री तापमान में बेहोश हो गया था। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया। एनएसजी को उम्मीद है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा तक कमांडो नई यूनिफॉर्म पहनने लगेंगे। एनएसजी के सूत्रों ने बताया कि अप्रैल 2026 में हुई एक घटना के बाद नई यूनिफॉर्म का फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात एक एनएसजी कमांडो ड्यूटी के दौरान ही बेहोश होकर गिर गया। उस दिन विजयवाड़ा में तापमान लगभग 44 डिग्री था। कमांडो ने काली ओवरऑल यूनिफॉर्म के ऊपर 6 किलो की बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी। सिर पर काली बेरेट थी और कमर पर छोटे हथियार लगे थे। कमांडो को हीटस्ट्रोक और थकान हुई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एनएसजी की क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स के कमांडरों ने घटना को गंभीरता से लिया।

फेस्टिव सीजन हुआ खत्म, अब यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज

2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 फीसदी एमडीआर देना होगा



नई दिल्ली (एजेंसी)। भाईदूज के त्योहार के साथ ही फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है। अब सबकी नजरें यूपीआई के नए नियमों पर हैं। कल से दुकानदार को 2,000 से ज्यादा का यूपीआई के जरिए लेने पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी चार्ज देना पड़ सकता है। पहले एनपीसीआई इन नए चार्जेस को 15 अक्टूबर से लागू करने वाला था, लेकिन त्योहारों के कारण इसे टाल दिया था।

कारोबारियों ने देशभर में विरोध किया था- सरकार के इस फैसले का देशभर के कारोबारियों और विपक्षी नेताओं ने विरोध किया था। विरोध दो स्तरों पर हुआ। विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक और आम लोगों पर असर को लेकर सवाल उठाए, जबकि कारोबारी संगठनों ने लागत बढ़ने और ग्राहकों पर बोझ पड़ने की आशंका जताई। उनका कहना था कि इससे छोटे कारोबारियों को ज्यादा नुकसान होगा।

सरकार के यूपीआई प्रपोजल की 3 बड़ी बातें

अगर ग्राहक दुकानदार को 2,000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करता है, तो दुकानदार को कुल रकम पर 0.4 फीसदी का एमडीआर चार्ज देना होगा। अगर ग्राहक 75,000 या उससे ज्यादा का बड़ा पेमेंट करता है, तो प्रतिशत के बजाय अधिकतम 300 का फ्लैट चार्ज लागू होगा। अगर ग्राहक रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस या फ्यूल पर 2,000 से ज्यादा का पेमेंट करता है, तो प्रति ट्रांजेक्शन 5 का फ्लैट चार्ज लगेगा। दिवाली के दौरान देश भर के बाजारों में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और सामानों की भारी बिक्री होती है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट बढ़ जाता है। कारोबारी संगठनों ने कहा था नया नियम लागू करने से पेमेंट में रुकावट आ सकती है।

अरे प्रदूषण हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे

दीपावली पर आतिशबाजी के विरोधियों को सीएम योगी ने दिया जवाब

लखनऊ (एजेंसी)। अगर पब्लिक एक दिन आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया। अरे हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा...। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें बुधवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं। सीएम योगी ने इस दौरान राजस्व विभाग के लिए चुने गए 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि का भी वितरण किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने दीपावली पर पटाखे जलाने के मुद्दे पर भी अपने अंदाज में जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा, साल 2017 से पहले कोई भी त्योहार आता था, चाहे होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, क्रिसमस हो, ईद हो, गुरु पर्व हो या मकर संक्रांति, हर त्योहार से पहले दंगे शुरू हो जाते थे। पीएसी बल दंगाइयों का काल था,



लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने यूपी पीएसी की 34 कंपनियां भी समाप्त कर दी। महीनों-महीनों तक कर्फ्यू लगे रहते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि धनतेरस के दिन पूरी मार्केट में चहल-पहल थी। अयोध्या का दीपोत्सव शानदार रहा।

मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था- अपने भाषण में सीएम योगी ने आगे कहा, आप सभी ने दीपावली मनाई और कुछ लोग कह रहे हैं कि पटाखे जलाने से प्रदूषण हो गया। अरे प्रदूषण हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो, जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उन्हें कोई नहीं बोलता। अगर लोगों ने एक दिन पटाखे जला लिए तो प्रदूषण हो गया, अरे हुआ है तो खत्म भी हो जाएगा। अच्छा हुआ, लोगों ने खूब आतिशबाजी की और दीपावली धूमधाम से मनाई।

ओवैसी और चंद्रशेखर ने बनाया यूपी के लिए नया मोर्चा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी-मार्च में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हो गया है। ओवैसी और चंद्रशेखर ने मिलकर उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बना लिया है। इस मोर्चे का ऐलान 12 नवंबर को होने की संभावना है। बताया जाता है कि एआईएमआईएम और एएसपी मिलकर उत्तर प्रदेश की 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा है कि, ऐसा विकल्प जनता के बीच होना चाहिए जो दलित मुस्लिम वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला हो और उनको राजनीतिक और सामाजिक न्याय दिलाने वाला हो। चीजें बहुत जल्द स्पष्ट होंगी।

नो कर्फ्यू-नो दंगा यूपी में अब सब चंगा

सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा, पहले की सरकारों में कर्फ्यू की वजह से व्यापार प्रभावित होता था, त्योहार प्रभावित होते थे। लेकिन, पिछले साढ़े 9 साल में नो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा। चंगा है तो अब नौकरियां भी उसी रफ्तार से निकल रही हैं। अकेले राजस्व विभाग में अभी तक 10836 नियुक्तियां हुई हैं। 1146 नियुक्तियां आज हो रही हैं। आने वाली 26 जनवरी तक हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा।

संक्षिप्त समाचार

पलामू में आदिम जनजाति के चार बच्चों का रेस्क्यू, बंधक बनाने का आरोप

पलामू, एजेंसी। जिला में मेदिनीनगर के श्रीराम पथ में एक घर से चार बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। सभी बच्चियों का उम्र छह वर्ष के करीब है और वह सभी आदिम जनजाति परिवार से हैं। बच्चियों को एक घर मे बंधक बनाकर रखा गया था और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। रेस्क्यू हुई सभी बच्चियां पलामू के चैनपुर के इलाके की हैं। दरअसल, सभी बच्चियां मेदिनीनगर के श्रीराम पथ के इलाके में एक घर में थीं, दो बच्चियां घर से भाग कर पड़ोस में चली गई थीं। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति और पलामू पुलिस को दी। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना के पुलिस और बाल कल्याण समिति मौके पर पहुंची थी और चार बच्चियों का रेस्क्यू किया।बाल कल्याण समिति ने सभी बच्चियों का बयान लिया है। बयान को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना को भी भेजा गया है। रेस्क्यू के बाद सभी बच्चियों को बालिका गृह भेजा गया है और उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया है। बच्चियों ने सीडब्लूसी को कई बातों की जानकारी दी है। बच्चियों को उनके गांव में रहने वाली एक महिला ने ही मेदिनीनगर में पहुंचा था।बच्चियों ने सीडब्ल्यूसी को बताया कि जिस घर में वे रहती थी। उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट भी की जाती थी। सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि चार बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार की काउंसलिंग की जाएगी और सभी बच्चियों का सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के थाना प्रभारी रितेश लकड़ा ने बताया कि सीडब्ल्यूसी का फर्द बयान मिला है पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 39 अधिकारियों का तबादला-पदस्थापन, अधिसूचना जारी

रांची, एजेंसी। झारखंड सरकार ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत भारतीय वन सेवा के 39 अधिकारियों का तबादला पदस्थापन हुआ है। साथ ही कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं।1994 बैच के राजकुमार वाजपेयी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा उन्हें पलामू, हजारीबाग, रांची और दुमका के निदेशक, प्रसार वानिकी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।वहीं 1995 बैच के जब्बर सिंह को स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैंपा, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके पहले जब्बर सिंह बिरसा जैविक उद्यान, रांची के निदेशक थे। वहीं कर्मा जिंपा भुटिया को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, रांची की जिम्मेदारी दी गई है।वहीं 1999 बैच के सिद्धार्थ त्रिपाठी को झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उनको अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफडीए रांची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं एसआर नटेश को मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, रांची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।वर्तमान में उनके पास मुख्य वन संरक्षक, वन प्राणी, रांची की जिम्मेदारी है। साथ ही एसआर नटेश पीटीआर के भी निदेश हैं। इसके अलावा आर थंगा पांडेयन को महाप्रबंधक लघु वन विकास निगम, हजारीबाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं पीआर नायडु को प्रोन्नति देते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची की जिम्मेदारी दी गई है।

यूसीओ बैंक में 5 करोड़ की डकैती कांड का खुलासा, हथियारों के साथ तीन गिरफ्तार

गिरिडीह, एजेंसी। जिले के राजधनवार में स्थित यूसीओ बैंक में हुई 5 करोड़ रुपये की डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लोडेड पिस्टल, देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और 2 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अब पुलिस लूटी गई रकम और सोने की बरामदगी में जुटी है। दरअसल, 5 नवंबर की दोपहर धनवार चौक स्थित यूको बैंक में 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों ने बैंक के लॉकर से करीब 5 करोड़ रुपये के सोने का पैकेट और करीब 11 लाख 50 हजार रुपये नकद लूट लिए थे। इस संबंध में धनवार थाना कांड संख्या 288/2026 दर्ज किया गया था। एसपी ने इस कांड के खुलासे के लिए खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जीतबाहन उरांव, सरिया-बगोदर धनंजय राम, और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय द्वितीय आरके राणा के नेतृत्व में 5 अलग-अलग विशेष अनुसंधान दल का गठन किया था। एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और नाकेबंदी करते हुए घटना को अंजाम देकर मोटरसाइकिल से भाग रहे अपराधियों का पीछा किया। इसी दौरान जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम-बरबदिया में अपराधी सड़क में बड़े गड्ढे के कारण मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर गिर गए। अपराधी बाइक को छोड़कर जंगल का लाभ उठाते हुए भाग गए। टीम ने चारों तरफ से जंगल की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के क्रम में जंगल से मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर झाड़ी में छिपाकर रखा गया लोडेड पिस्टल बरामद की गई। एसपी डॉ. बिमल ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद रिजवान से पूछताछ के बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बड़वारा जंगल से सुल्तान अली उर्फ रॉकी को 1 देसी कट्टे के साथ और आयुष पांडेय को 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दोनों की निशानदेही पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र से घटना में प्रयुक्त एक वाहन को भी जब्त किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त में मोहम्मद रिजवान (पिता- हयात अली, ग्राम-सतसंग सुरा तिलौना, थाना-नगर, जिला-देवघर), सुल्तान अली उर्फ रॉकी (पिता मोहम्मद सब्बीर हुसैन, ग्राम-चपुआडीह, थाना-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह) एवं आयुष पांडेय (पिता स्व। जयकांत पांडेय, ग्राम-गुड़ली पत्थर, पो।-सतसंग, थाना-नगर, जिला-देवघर) शामिल हैं।

छठ महापर्व को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट

सभी जिलों में पूरी की गई फोर्स की मांग, घाटों पर रहेगी विशेष निगरानी

रांची, एजेंसी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है। राज्यभर में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। जिलों के पुलिस अधीक्षकों की ओर से सुरक्षा के लिए जितने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी, उसे पूरा कर दिया गया है। इसके साथ ही छठ घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी तैयारी की गई है।

छठ महापर्व के दौरान 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्याकालीन अर्घ्य और 16 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। इन चारों दिनों में पुलिस और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय का उद्देश्य है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के छठ महापर्व मना सकें। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती से लेकर स्थानीय शांति समितियों के सहयोग तक सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।



आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि छठ पूरे देश में मनाया जाने वाला बहुत ही पवित्र पर्व है। इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है। सभी जिलों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली गई है। जहां जितने पुलिस बल की आवश्यकता बताई गई थी, वहां उस मांग को पूरा कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जा रही है।

नरेंद्र सिंह ने बताया कि छठ पर्व को लेकर विशेष रूप से शांति समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में स्थानीय बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है। उनसे पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करने और अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने की अपील की गई है। किसी भी तरह की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने को कहा गया है। पुलिस का मानना है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्व के दौरान बेहतर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में छठ घाटों की स्थिति का पहले से निरीक्षण करने और वहां साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। खतरनाक घाटों की पहचान कर वहां बैरिकेडिंग, गोताखोर, नाव और सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। नदी, तालाब और डैम में पानी की अधिक गहराई वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है, ताकि अर्घ्य देने के दौरान किसी तरह की दुर्घटना न हो। घाटों और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के साथ जन सूचना प्रणाली भी दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है।

छठ घाटों पर बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंचती हैं। इसे देखते हुए महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाएगी। छिनतई, चोरी, छेड़खानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। जरूरत के अनुसार सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे।

आईजी नरेंद्र सिंह ने कहा कि छठ के दौरान सामान्य तौर पर अपराध की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस लगातार सतर्क रहेगी और हर स्थिति पर नजर रखेगी और किसी भी तरह की शरारत या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

छठ के दौरान घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं और वाहनों की भीड़ बढ़ जाती है। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। भीड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करने, अग्निशमन दस्ते को तैयार रखने और सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर रहेगी, ताकि किसी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश न हो।

झारखंड में स्कूल से बाहर बच्चों की तलाश में घर-घर पहुंचेंगे शिक्षक, 33.39 लाख बच्चों को मिलेंगे वाटरप्रूफ बैग

रांची, एजेंसी। झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा है।

इसके तहत एक ओर स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान के लिए राज्यव्यापी घर-घर सर्वे शुरू किया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के 33।39 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त वाटरप्रूफ स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने के साथ स्कूलों में नामांकन और नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना है।

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 10 नवंबर 2026 से बाल पंजीकरण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह अभियान 1 जनवरी 2027 तक चलेगा, जबकि 10 जनवरी तक आंकड़ों का अंतिम सत्यापन और प्रमाणीकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत तीन से 18 वर्ष तक के बच्चों की पहचान की जाएगी। सर्वे में ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने कभी स्कूल में नामांकन नहीं कराया है या किसी कारण से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है।

इस अभियान के लिए डहर 2।0 डिजिटल पोर्टल और एप का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों से संबंधित जानकारी जुटा रहे हैं और उसे ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। छह से 18 वर्ष तक के बच्चों के पुराने स्कूल रिकॉर्ड, पहचान संबंधी विवरण और पढ़ाई छोड़ने के कारणों की जानकारी भी बाल पंजी में दर्ज की जा रही है। इससे स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी।

सर्वे को निर्धारित समय में पूरा करने की जिम्मेदारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को दी गई है।



अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन समितियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सर्वे में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और वेतन रोकने जैसे प्रावधान भी निर्देशों में शामिल किए गए हैं। यह अभियान राज्य में जीरो ड्रॉपआउट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दूसरी ओर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्कूल किट योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले 33,39,234 बच्चों को मुफ्त वाटरप्रूफ स्कूल बैग देने की तैयारी है। इस योजना के लिए 50।63 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। बैग की आपूर्ति प्रखंड स्तर से स्कूलों तक किए जाने की व्यवस्था है।

बच्चों की कक्षा के अनुसार बैग का रंग भी अलग-अलग रखा गया है। कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों को गुलाबी, कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों को आसमानी और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को गहरे नीले रंग के बैग दिए जाएंगे। बैग वाटर रेसिस्टेंट कपड़े से तैयार किए गए हैं। इनमें बच्चों की सुविधा के लिए कुशन वाली पट्टियां, पानी की बोतल रखने के लिए अलग पॉकेट और 4म3 इंच की पारदर्शी नेमप्लेट पॉकेट होगी। इसमें विद्यार्थी का नाम, स्कूल, रोल नंबर और अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज किया जा सकेगा। बैग की क्षमता 25 किलोग्राम वजन सहने की बताई गई है।

नवंबर में 50।63 करोड़ रुपये के बजट और टेंडर प्रक्रिया को प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद बैग की आपूर्ति की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विभागीय निर्देश के अनुसार, आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही बच्चों को बैग उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अप्रैल से मई के बीच सभी स्कूलों में बैग वितरण पूरा किया जाना है, ताकि विद्यार्थियों को नई किताबों के साथ नए बैग भी मिल सकें।

आमटाल सहित पूरे कोयलांचल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई-बहन के अटूट प्रेम का महापर्व 'भाई फोटा'

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता ,रांची/

बलियापुर (धनबाद), ।भाई-बहन के असीम स्नेह, विश्वास और दीर्घायु की कामना का पावन पर्व 'भाई फोटा' (भैया दूज) बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आमटाल पंचायत सहित पूरे कोयलांचल में अत्यंत श्रद्धा और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के कपाल (माथे) पर चंदन और काजल का तिलक (फोटा) लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की। के दौरान पारंपरिक बंगाली और कोयलांचल संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली। बहनों ने 'भाइयेर कपाले दिलाम फोटा, यमेर दुआरे पड़लो कांटा' के पारंपरिक मंत्रोच्चार के साथ भाइयों की आरती उतारी और उन्हें मिठाइयाँ खिलाईं। वहीं, भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार भेंट कर जीवन भर उनकी रक्षा और सुख-दुख में साथ निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव महतो ने तमाम कोयलांचल और सिंदरी वासियों को भाई फोटा की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, 'भाई फोटा केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध

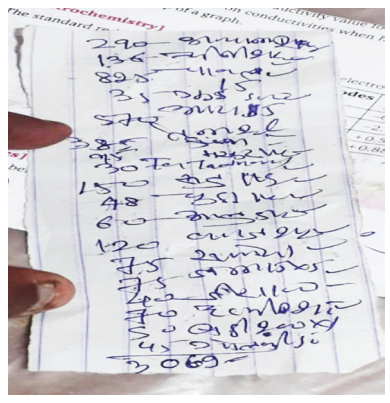


सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। कोयलांचल की इस पावन धरती पर यह पर्व आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को और अधिक मजबूत करता है। ' 5उत्सव के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय और पारिवारिक माहौल बना रहा और लोगों ने एक-दूसरे को पर्व की बधाइयाँ दीं।

भाई दूज पर मानवता की मिसाल: पीड़ित बच्ची के परिवार को मिला एक महीने का राशन

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद। बलियापुर भाई दूज (भाई फोटा) के पावन अवसर पर हरिओम सेवा संस्था ने एक बार फिर मानव धर्म की अनूठी मिसाल पेश की। संस्था के सदस्यों ने गंभीर बीमारी से जूझ रही नन्हीं बच्ची राजनंदनी के परिवार को भाई दूज के उपहार स्वरूप पूरे एक महीने की राशन सामग्री उपलब्ध कराई। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी संस्था ने राजनंदनी के वेल्लूर में इलाज के लिए रेल टिकट, ठहरने की व्यवस्था और आर्थिक मदद की थी। उस समय संस्था के संस्थापक सदस्य



विनोद सिंह ने भविष्य में भी मदद का वादा किया था, जिसे उन्होंने संकट की इस घड़ी में निभाया।



राजनंदनी के पिता ने आर्थिक तंगी और घर में राशन खत्म होने की समस्या को लेकर सिंदरी विधायक प्रतिनिधि सह संस्था के मीडिया प्रभारी शीतल दत्ता से संपर्क किया था। शीतल दत्ता ने तुरंत संस्थापक सदस्य विनोद सिंह से विचार-विमर्श कर त्वरित कदम उठाया। परिवार को नजदीकी दुकान से पूरे महीने का राशन - चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, सत्तू, चूड़ा, साबुन, मसाला, बिस्किट आदि दिलवाया गया और दुकान के क्यूआर कोड पर तुरंत पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। संस्था के संस्थापक सदस्य विनोद सिंह ने बताया कि संस्था के पास कोई बड़ा बाहरी फंड नहीं है। सभी सदस्य अपने निजी पॉकेट खर्च से पैसे बचाकर आपसी सहयोग से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस नेक कार्य के लिए संस्था के सभी सदस्यों ने भविष्य में भी मानव सेवा जारी रखने का संकल्प दोहराया।

रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने डोरंडा स्थित मां काली पूजा पंडाल में किए दर्शन, जिले वासियों की सुख-समृद्धि की कामना की



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची।जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने डोरंडा स्थित मां काली पूजा समिति के पूजा पंडाल पहुंचकर मां काली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने मां काली से समस्त जिलेवासियों के सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं शांति की कामना की। इस दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने काली पूजा के सफल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए गए सहयोग एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आभार व्यक्त किया। समिति के सदस्यों ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग एवं समन्वय से पूजा का आयोजन बेहतर एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आपसी सौहार्द, भाईचारे एवं शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की।

छठ महापर्व को लेकर रांची प्रशासन मुस्तैद, रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने किया विभिन्न घाटों का निरीक्षण



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। छठ महापर्व का आयोजन सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने मंगलवार को शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा



लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा समितियों के सदस्यों से बातचीत कर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि छठ घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा सभी सुरक्षात्मक उपाय समय से सुनिश्चित किए जाएं। रास्ते, सफाई और रोशनी पर विशेष जोर उपायुक्त ने घाटों तक पहुंचने वाले एप्रोच रोड को डस्ट भरकर समतल एवं सुगम बनाने, साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, बिजली की सुरक्षित व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। नगर निगम क्षेत्र के बाहर स्थित घाटों पर भी सुरक्षा एवं सुविधाओं से संबंधित सभी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर पारस राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर पारस राणा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार रजत सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

इन घाटों का किया निरीक्षण

रांची उपायुक्त ने हातमा, कांके डैम, मधुकम, हटनिया, बड़ा तालाब, जेल तालाब, चडरी, अरगोड़ा, धुर्वा, बटन तालाब, बनस तालाब (चुटिया) एवं पावर हाउस तालाब स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया।

3 फीट गहराई पर होगी बैरिकेडिंग

घाटों पर जलस्तर एवं पानी की गहराई को देखते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पानी में तीन फीट की गहराई के बाद बैरिकेडिंग/घेराबंदी सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालु निर्धारित सुरक्षित सीमा से आगे न जा सकें। खतरनाक एवं गहरे जल वाले स्थानों को चिन्हित कर चेतावनी संकेतक लगाने का भी निर्देश दिया गया।

NDRF-SDRF की टीम रहेगी तैनात

अत्यंत संवेदनशील घाटों पर NDRF एवं SDRF की टीम तैनात की जाएगी। इसके अलावा गोताखोर, बचाव दल एवं अन्य आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी समितियों को गोताखोरों के मोबाइल नंबर साझा करने के निर्देश भी दिए गए।

संक्षिप्त समाचार

धनबाद में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र का खेल उजागर, पंचायत भवन में संचालित प्रज्ञा केंद्र सील

धनबाद, एजेंसी। सरकारी प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। होमगार्ड बहाली के दौरान एक अभ्यर्थी द्वारा जमा कराया गया आवासीय प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम लोकेश बारंगे ने पाथरकुआं पंचायत भवन में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर यानी प्रज्ञा केंद्र पर छापेमारी की। जांच के बाद केंद्र को सील कर दिया गया है। वहीं, संबंधित संचालक की सीएससी आईडी निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। प्रशासन ने मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल, होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थी कृष्णपद सोरेन, पिता देबु सोरेन, निवासी बड़बाड़ी गांव, थाना निरसा ने अपना आवासीय प्रमाण पत्र जमा किया था। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अंचल कार्यालय कालियासोल को प्रमाण पत्र की वैधता पर संदेह हुआ। इसके बाद झारसेवा पोर्टल पर ऑनलाइन जांच कराई गयी। जांच में खुलासा हुआ कि संबंधित प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से कभी जारी ही नहीं किया गया था। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक आवेदन में त्रुटि होने के कारण उसे लंबित रखा गया था अथवा वापस कर दिया गया था। इसके बावजूद अभ्यर्थी को डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया गया। अभ्यर्थी ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2023 में उसने गांव के ही सीएससी संचालक अभिजीत दास के माध्यम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। इसके लिए संचालक को 500 रुपये भी दिए थे। आरोप है कि बाद में उसे सरकारी दस्तावेज की तरह दिखने वाला फर्जी प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया। भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने से अभ्यर्थी का भविष्य भी संकट में पड़ गया। शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की।

दिन में बंद घरों की रेकी, रात में चोरी, हरियाणा का शातिर चोर रांची में गिरफ्तार, तीन साथी भी पकड़े गए

रांची, एजेंसी। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला शातिर चोर आकाश महतो उर्फ आकाश कुमार समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर दो ज्वेलरी दुकानों से चोरी के गहने बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपी के घर से सोने-चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन जब्त किया गया। बरामद सोने-चांदी के जेवरों की अनुमानित कीमत करीब 3।70 लाख रुपये बताई गई है। रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि आकाश महतो हरियाणा के कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वहां चोरी की वारदातों के बाद वह रांची आ गया था और रातू थाना क्षेत्र के आमटांड़ में अपनी पत्नी के साथ किराये के मकान में रहने लगा था। उसने अपनी पहचान छिपाकर यहां ठिकाना बनाया था, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। गिरोह के सदस्य बंद घरों को निशाना बनाते थे। खास बात यह है कि आकाश दिन के समय ही चोरी की वारदातों को अंजाम देने में माहिर था। रातू थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसपी ग्रामीण ने पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) द्वितीय अजय आर्यन के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया था। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर रातू काटीटांड़ स्थित अलंकार ज्वेलर्स और जेपी जेवर दुकान से चोरी के गहने बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने चोरी के जेवर इन दुकानों में बेच दिए थे। पुलिस ने इस मामले में आकाश महतो के अलावा रातू के विनय कुमार वर्मा, धनबाद के विनायक कुमार सोनी और रातू के ही दीपक उरांव उर्फ लड्डू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों ने रातू थाना में दर्ज कांड संख्या 373/26 के अलावा चोरी के तीन अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनमें रातू थाना कांड संख्या 246/26, 327/26, 315/26 और 378/26 शामिल हैं। पुलिस ने जेपी जेवर दुकान से चांदी के दो जोड़ी पायल, एक चांदी की चेन, एक सोने का मंगलसूत्र और पांच सोने की नोजपिन बरामद की हैं।

सोनिया गांधी की किताब पर निशिकांत दुबे का हमला, संजय गांधी को विलेन और राजीव गांधी को हीरो बताने का लगाया आरोप

देवघर, एजेंसी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की किताब पर सवाल उठाते हुए तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि किताब में लिखी गई बातों से स्पष्ट होता है कि सोनिया गांधी को भारतीय संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। सांसद निशिकांत दुबे ने किताब में संजय गांधी और राजीव गांधी के संदर्भ में लिखी गई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें संजय गांधी को विलेन और राजीव गांधी को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किताब में लिखी गई बातें सही हैं, तो वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी को चुनाव क्यों लड़ाया गया था? वहीं, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से जुड़े प्रसंग का उल्लेख करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्ष 1989 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब सोनिया गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।उन्होंने नेहरू परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी से जुड़े प्रसंग पर भी सवाल उठाए। निशिकांत दुबे ने कहा कि जब मेनका गांधी को परिवार से बाहर जाना पड़ा, तब किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। जबकि भारतीय पारिवारिक परंपराओं में विधवा महिला को विशेष सम्मान देने की मान्यता रही है। सांसद ने आगे कहा कि भारतीय संयुक्त परिवार में रहने के दौरान कई तरह के त्याग और समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन सोनिया गांधी की किताब में इन पारिवारिक परंपराओं और परिस्थितियों को लेकर कोई व्यापक दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें सोनिया गांधी स्वयं को सही साबित कर रही हैं, जबकि उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया है, जिनमें उनकी भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं।

निशा भगत आत्महत्या मामला:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सीबीआई जांच की अनुशंसा

रांची, एजेंसी। आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की अनुशंसा कर दी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात 10 बजकर 10 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की।

पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर झारखंड की राजनीति में लगातार बयानबाजी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही थी। मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से रांची में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाब देने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की।

भाजपा की प्रमुख मांगों में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराना शामिल था। खास बात यह रही कि सरकार का यह निर्णय उस दिन आया, जब कुछ घंटे पहले ही रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने मीडिया





से बात करते हुए भरोसा दिलाया था कि स्ढुञ्ज पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है। इसी वजह से पिठोरिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है।

इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस फैसले को भाजपा के दबाव का नतीजा बताया है। आदित्य साहू का कहना है कि निशा भगत की आत्महत्या की खबर मिलते ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया था। एसटी मोर्चा ने पुतला दहन, मशाल जुलूस से लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी। एसटी मोर्चा सहित पूरी भाजपा ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया।

आगामी दिनों में झारखंड बंद और कैंडल मार्च सहित कई आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। भाजपा के इस लगातार आंदोलन का ही असर है कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा को भरोसा है कि सीबीआई जांच से निशा भगत के परिजनों को न्याय मिलेगा। इस मामले में जो भी दोषी होंगे, वे किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे।

बता दें कि 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया स्थित अपने आवास पर निशा भगत ने फेसबुक लाइव किया था। करीब 10 से 11 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जमीन पर कथित कब्जे, जमीन माफिया और प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने जैसे मुद्दे उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जमीन से जुड़े मामलों में आवाज उठाने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर उनकी छवि खराब किए जाने और उन्हें दलाल कहे जाने से भी वह आहत नजर आई थीं। इसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आई थी। मौत के बाद उनके पिता ने थाने में लिखित शिकायत देकर प्रताड़ना, सामाजिक रूप से बदनाम करने और झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश के आरोप लगाए थे। शिकायत में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद किया गया था। साथ ही पिठोरिया थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे।इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। वहीं, भाजपा ने इसे आदिवासी सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा था।

दलित के कंधे पर बैठकर नदी पार कर रहे थे आरजेडी विधायक, संतुलन बिगड़ते ही गिरे धड़ाम!

पलामू, एजेंसी। झारखंड के पलामू जिले के बिश्रामपुर अंतर्गत घासीदाग में राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह का एक वीडियो और मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां धुरिया नदी पार करने के दौरान विधायक एक दलित व्यक्ति के कंधे पर सवार हो गए। हालांकि, नदी के बीच धारा में संतुलन बिगड़ने के कारण विधायक और उन्हें कंधे पर उठाने वाला शख्स, दोनों ही पानी में गिर गए। गनीमत रही कि नदी में पानी घुटने तक ही था और इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

घासीदाग पंचायत में एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बिश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह को आमंत्रित किया गया था। विधायक सोमवार देर शाम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गांव पहुंचे थे। घासीदाग गांव में प्रवेश करने के लिए धुरिया नदी को पार करना अनिवार्य था। नदी में पानी होने के कारण विधायक खुद पैदल जाने के बजाय एक दलित ग्रामीण के कंधे पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति विधायक को लेकर नदी के बीच पहुंचा, तेज बहाव और लड़खड़ाते कदमों के कारण दोनों पानी में गिर पड़े।

इस पूरी घटना को लेकर विधायक नरेश प्रसाद सिंह के प्रतिनिधि धनंजय पासवान ने कहा कि वे मामले की पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, जिसके बाद ही आधिकारिक बयान देंगे। आपको बता दें कि घासीदाग पंचायत बारिश के दिनों में मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट जाती है। यह इलाका चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और यहां के ग्रामीण लंबे समय से सरकार और प्रशासन से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं।



घासीदाग पंचायत की मुखिया अंजू देवी ने इस घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा, 'एक दलित व्यक्ति के कंधे पर बैठकर नदी पार करना विधायक की सामंती मानसिकता को दर्शाता है। गांव में पुल नहीं होने के कारण ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विधायक ने इस पर कभी संज्ञान नहीं लिया। अब जब विधायक खुद नदी में गिर गए हैं, तो उम्मीद है कि उन्हें जनता के इस रोजमर्रा के दर्द और समस्या का अहसास होगा। '

इस घटना के बाद बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने विधायक व सरकार को आड़े हाथों लिया है, बहुजन समाज पार्टी के नेता राहुल दुबे ने कहा कि आम जनता बारिश के मौसम में इलाज तक नहीं करा पाती है। विधायक को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन वे क्षेत्र की मूलभूत समस्या दूर नहीं कर पाए। जनता की समस्या हल करने के बजाय वह एक दलित की पीठ पर बैठकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, भाजपा पलामू के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'झारखंड की वर्तमान सरकार आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं वर्गों का हो रहा है। चाहे निशा भगत की मौत का मामला हो या बिश्रामपुर की यह शर्मनाक घटना, यह सरकार की संवेदनहीन मानसिकता को उजागर करती है। लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है और आम जनता के दर्द से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। '

सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी करेंगे पीडीएस की निगरानी, जेएसएफसी ने रिटायर्ड ऑफिसर से मांगा आवेदन

रांची, एजेंसी। कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी झेल रहा राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने जन वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों के तौर पर संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञापन के तहत भारतीय खाद्य निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों में से सभी 24 जिलों में 1 पदों के हिसाब से कुल 24 क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट की संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के भंडारण, जांच और मानकों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए चयनित होने वाले इन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट का कार्यकाल अधिकतम तीन साल या 65 वर्ष होगा। हालांकि 2 साल कार्यकाल बढ़ाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, लेकिन अधिकतम उम्र 65 ही होगा चयनित विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर दो वर्ष कार्यकाल विस्तार का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच, मूल्यांकन भंडारण और संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का कार्य अनुभव उन्हें हों और उनकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष हो।

झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में कर्मचारी से लेकर पदाधिकारियों की भारी कमी है। हालत यह है कि स्वीकृत 618 पदों में अधिकांश खाली हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न पद खाली होने की वजह से प्रभारी के भरोसे निगम का कामकाज किसी तरह से चल रहा है। हालत यह है कि जिला प्रबंधक, सहायक जिला प्रबंधक आदि पद रिक्त हैं। इसके लिए जिला स्तर पर आपूर्ति पदाधिकारी को जिला मैनेजर का प्रभार दिया गया है और प्रखंडों में स्थित गोदाम की देखरेख का जिम्मा जिला स्तर से वहां के कर्मचारियों को दिया गया है। ऐसे में नई नियमावली बनने तक संविदा पर नियुक्त कर तत्काल कामकाज चलाने की तैयारी की गई है।

धनबाद में हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख

धनबाद, एजेंसी। जिले के कतरास में स्वास्तिक सिनेमा रोड स्थित एक हार्डवेयर दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखे हार्डवेयर व टाइल्स समेत तमाम सामान धू-धू कर जलने लगे। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की शुरुआती आशंका जताई जा रही है। दुकानदार के मुताबिक, इस घटना में करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

घटना मंगलवार रात की है, 8: 30 बजे दुकान बंद कर घर पहुंचने के बाद दुकानदार दिनेश भगत को दुकान में आग लगने की सूचना मिली। वह आनन-फानन में मौके पर



पहुंचे, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटों की तीव्रता के सामने उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए।

सूचना मिलने के बाद कतरास थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं, धनबाद से दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने के लगभग दो घंटे बाद अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच सकी। इसके बाद आग बुझाने का अभियान शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। दमकल की गाड़ियों का पानी समाप्त होने के बाद स्थानीय विधायक की ओर से पानी के टैंकर भी मंगवाए गए।

आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुकान में रखा सामान देखते ही देखते जलकर बर्बाद हो गया। दुकानदार दिनेश भगत अपनी आंखों के सामने वर्षों की मेहनत की कमाई को राख में तब्दील होते देख भावुक हो गए। घटना के बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला।

फिलहाल, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती तौर पर इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के बाद बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने भी अग्निशमन व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बाघमारा क्षेत्र में एक बड़ी आबादी है, लेकिन इतने बड़े इलाके में दमकल विभाग का अपना कार्यालय नहीं है। आग लगने की स्थिति में लोगों को धनबाद मुख्यालय से दमकल की गाड़ियों के आने का इंतजार करना पड़ता है। धनबाद से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर दमकल वाहन घटनास्थल तक पहुंचते हैं।

18 नवंबर से सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होगा 'एक और अवसर कैंप'

रांची, एजेंसी। झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अंतिम चरण में है। शामिल ऐसे पात्र मतदाताओं, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, को अंतिम मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस उद्देश्य से आगामी 18 नवंबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक 'एक और अवसर कैंप' का आयोजित किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के। रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कैंप के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव पाठशाला की छठी बैठक भी आयोजित की जाएगी। सूची में शामिल ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जो संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं तथा जिन्होंने अभी तक प्रपत्र-6 नहीं भरा है। ऐसे मतदाताओं के साथ विचार-विमर्श कर उनकी पात्रता का सत्यापन करते हुए उन्हें अंतिम रूप से चिह्नित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित ERO द्वारा ऐसे मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र एवं घोषणा पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपात्र पाए गए व्यक्तियों की नामवार सूची प्रपत्र-3 में सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों में चल रहे एसआईआर की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

रांची में एसआईआर कार्य में लापरवाही पर बुंडू एलआरडीसी और सीओ को शोकॉज

रांची, एजेंसी। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।

मंगलवार को समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने समीक्षा बैठक के दौरान बुंडू के छवि बाला और अंचल अधिकारी हंस हेम्ब्रम को कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर शोकॉज करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अगले तीन दिनों में कार्य में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिले के औसत प्रदर्शन से नीचे रहने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को भी शोकॉज करने का निर्देश दिया गया।

इस बैठक में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने स्ढुक्रके तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। इसलिए सभी अधिकारी मतदाता सूची की गहन जांच करें,



ताकि अंतिम प्रकाशन के समय किसी तरह की त्रुटि नहीं रहे।

उपायुक्त ने तार्किक विसंगति और नो मैपिंग से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने को कहा। उन्होंने सभी ERO को अपने अधीनस्थ कर्मियों के काम की नियमित और करीबी निगरानी करने का निर्देश दिया। फॉर्म-6 के निष्पादन की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा स्ढुक्रके दौरान प्राप्त प्रपत्रों, नोटिस, सुनवाई से जुड़े दस्तावेजों और निष्पादन प्रतिवेदनों को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने को कहा गया।

निर्वाचन कार्यों की समीक्षा के साथ उपायुक्त ने छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों और छठ घाटों की साफ-सफाई का निरीक्षण करने तथा छठ समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

उपायुक्त ने सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत स्तर के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार ही सरकार की छवि बनाता है। आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनकर उनका समयबद्ध समाधान किया जाए। सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों की भूमिका पर पूरी तरह रोक लगाने और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का निर्देश भी दिया।

उपायुक्त ने आदिवासी भूमि की सुरक्षा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी अंचल में आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत या मामला सामने आने पर संबंधित अंचल अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। सभी ष्ठह्व को अपने क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों की विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

बिहार में झारखंड से पहुंचाई जा रही थी 50 लाख की शराब, चालक गिरफ्तार

नालंदा, एजेंसी। शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना की संयुक्त टीम ने मिनी ट्रक से 3200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है।बरामद शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई बिहार शरीफ के डीटीओ कार्यालय के समीप एनएच-20 पर की गई। शराब की यह खेप झारखंड से बिहार शरीफ के रास्ते पटना ले जाई जा रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने वाहनों की सघन जांच शुरू की।जांच के दौरान एक संदिग्ध मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, तो ट्रक में ऊपर से भूसे की 40 बोरियां लदी मिलीं। वहीं, जब टीम ने भूसे की बोरियों को हटाकर जांच की तो 395 कार्टून शराब बरामद हुई। बरामद कार्टून में करीब 3200 लीटर अंग्रेजी शराब की मात्रा पाई गई। शराब को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा गया था। गिरफ्तार चालक की पहचान हरियाणा के भिवानी निवासी पवन कुमार के रूप में की गई है। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार चालक से पूछताछ की जा रही है। शराब की खेप किसके कहने पर और किसे पहुंचाई जानी थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

सम्राट सरकार ने शिक्षकों को दिया तोहफा, छठ से पहले मिलेगा लंबित वेतन

पटना, एजेंसी। बिहार के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान छठ से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी का वेतन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक में राज्य के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की गई। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि ज्यादातर शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि, कुछ कर्मचारियों का वेतन अब भी लंबित है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शेष कर्मियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी से कर्मचारियों को परेशानी होती है। खासकर छठ जैसे बड़े पर्व से पहले कर्मचारियों को उनके लंबित वेतन का भुगतान मिलना जरूरी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस मामले को प्राथमिकता देने और भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। साथ ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित बनाने पर भी जोर दिया, ताकि भविष्य में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए इंतजार ना करना पड़े। गौरतलब है कि छठ महापर्व से पहले वेतन भुगतान का मुद्दा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में शिक्षा विभाग की इस पहल से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका वेतन अब तक लंबित है।

होटल में चल रहा था देह व्यापार, मैनेजर गिरफ्तार, नाबालिग समेत तीन लड़कियां मुक्त

सीतामढ़ी, एजेंसी। बिहार की सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निर्देश पर मानव तस्करी निरोध इकाई और स्पेशल क्राइम टीम ने मेहसौल थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर देह व्यापार के अवैध धंधा का पर्दाफाश किया है। इस दौरान एक नाबालिग समेत तीन लड़कियों को मुक्त कराया गया, जबकि मौके से दो ग्राहकों और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। शहर के बीचोंबीच स्थित होटल में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान टीम को कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद होटल से तीन लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीतामढ़ी शहर में होटल की आड़ में कथित देह व्यापार का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ गई है। मेहसौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर में स्थित आरती होटल में अनैतिक गतिविधियां संचालित किए जाने की आशंका पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की रणनीति तैयार की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस की मानव तस्करी निरोध इकाई और स्पेशल क्राइम की टीम ने होटल में अचानक दबिश दी। इस कार्रवाई से होटल में मौजूद लोगों के बीच अफरातफरी मच गई। पुलिस टीम ने होटल के कमरों और परिसर की जांच-पड़ताल की। इसी दौरान एक नाबालिग समेत तीन लड़कियों को वहां से मुक्त कराया गया। पुलिस ने मौके से दो ग्राहकों और होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने होटल से गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच का दायरा होटल तक सीमित नहीं रहने की संभावना है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो ग्राहकों के साथ होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केरलम के बाद पटना में अब वाटर मेट्रो

पटना, एजेंसी। पटना में गंगा नदी पर सफर करने का अंदाज अब बदलने जा रहा है। छठ महापर्व के मौके पर राजधानी के लोगों को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। मंगलवार को गंगा नदी में दीघा घाट से एनआईटी घाट के बीच वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीघा घाट पर इस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। वाटर मेट्रो की शुरुआत के साथ ही पटना के लोगों को सड़क के अलावा अब गंगा के रास्ते भी सफर करने का एक नया विकल्प मिल गया है।

वाटर मेट्रो सेवा का लाभ आम लोग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उठा सकेंगे। इसके लिए वयस्क यात्रियों का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जबकि पांच से 12 साल तक के बच्चों के लिए टिकट की कीमत 25 रुपये रखी गई है। सभी पर्यटक अभी दीघा घाट पर काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र ही ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।

वाटर मेट्रो का परिचालन पटना के दीघा (मीनार घाट) से प्रारंभ होगा तथा यह गांधी घाट पहुंचेगा। इसके बाद गांधी घाट से फिर दीघा के लिए प्रस्थान करेगा तथा शाम को दीघा (मीनार घाट) पहुंचेगा। यानी अब लोग कम खर्च में गंगा की लहरों के बीच सफर करने के साथ-साथ राजधानी के नदी किनारे बसे इलाकों का नजारा भी देख सकेंगे।



यह कैटामरान वेसल हाइब्रिड इंजन से लैस है। इसमें उपलब्ध बैटरी को चार्ज करने के लिए पटना के दीघा (मीनार घाट) एवं गांधी घाट पर फास्ट चार्जर एवं शोर चार्जर की व्यवस्था की गई है। भविष्य में इसका संचालन कंगन घाट तक विस्तारित किया जायेगा।

कैटामरान वेसल 50 यात्रियों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जलयान है। यह मुख्यतः विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है। इसके संचालन से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण नहीं होगा। यह गंगा नदी में पर्यटकों को एक रोमांचक एवं सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। इस कैटामरान वेसल में उद्घोषणा प्रणाली, वातानुकूलन सुविधा, शौचालय, व्हील चेयर एवं अन्य आवश्यक आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

फिलहाल वाटर मेट्रो का संचालन दीघा घाट से हड्डूज्ञ घाट के बीच करीब 9।5 किलोमीटर के रूट पर किया जाएगा। इस रूट पर आधुनिक और वातानुकूलित मेट्रो बोट चलाई जाएगी। सेवा का संचालन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की निगरानी में होगा। इसका उद्देश्य केवल गंगा में सैर-सपाटा कराना नहीं, बल्कि जलमार्ग को परिवहन के एक बेहतर विकल्प के रूप में विकसित करना भी है। आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार होता है तो शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच आवागमन के नए रास्ते खुल सकते हैं।

वाटर मेट्रो को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। बोट में एसी की व्यवस्था होगी, ताकि गर्मी के मौसम में भी यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके। इसके अलावा शौचालय, उद्घोषणा प्रणाली और व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

एक बार में यात्रियों की बैठने की क्षमता को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। उपलब्ध इंफोग्राफिक्स के मुताबिक बोट में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता बताई गई है, जबकि शुरुआती जानकारी में करीब 100 यात्रियों के सफर करने की बात कही गई थी। ऐसे में वास्तविक क्षमता की आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी।

इस वाटर मेट्रो की एक खासियत इसकी आधुनिक चार्जिंग व्यवस्था भी है। बोट की बैटरी चार्ज करने के लिए गांधी घाट पर विशेष सुपर चार्जर लगाया गया है। दावा है कि इस सुपर चार्जर की मदद से बोट को महज 10 से 15 मिनट में चार्ज किया जा सकेगा। इससे बोट के संचालन में लगने वाला समय कम होगा और सेवा को लगातार जारी रखने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित इस व्यवस्था को गंगा में आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

बिहार पक्षी गणना में भागलपुर रहा टॉप, घटोरा वेटलैंड बना 23000 पक्षियों का बसेरा

भागलपुर, एजेंसी। बिहार राज्य पक्षी गणना 2025 की रिपोर्ट में भागलपुर जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस व्यापक सर्वेक्षण के दौरान जिले में कुल 23,268 पक्षी दर्ज किए गए हैं। पक्षियों की यह भारी संख्या इस क्षेत्र के बढ़ते पारिस्थितिक महत्व को दर्शा रही है। इस गणना के दौरान क्षेत्र में पक्षियों की 119 अलग-अलग प्रजातियों की पहचान की गई है। आंकड़े बताते हैं कि भागलपुर की गंगा से जुड़ी आर्द्रभूमियां, दियारा क्षेत्र और स्थानीय जलाशय पक्षियों के अनुकूल आवास बन चुके हैं। यह प्राकृतिक परिवेश विदेशी प्रवासी पक्षियों को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर रहा है।

नवगछिया अनुमंडल में स्थित घटोरा वेटलैंड पूरे बिहार में प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी पनाहगाह बनकर सामने आया है। वर्ष 2025 की गणना में केवल इसी एक साइट पर कुल 9,046 पक्षी दर्ज किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या के साथ यह वेटलैंड बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी



अभ्यारण्य क्षेत्र बन गया है।

घटोरा वेटलैंड में दर्ज कुल पक्षियों में से 6,968 प्रवासी मेहमान हैं, जबकि 2,078 स्थानीय पक्षी हैं। इसका मतलब है कि घटोरा में मौजूद कुल पक्षियों में करीब 77 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी प्रवासी पक्षियों की है। यह स्थल दुनिया के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले पक्षियों का पसंदीदा शीतकालीन घर बना हुआ है।

हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस बार घटोरा में पक्षियों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। वर्ष 2024 में यहां कुल 10,110 पक्षी दर्ज किए गए थे। इस मामूली गिरावट के बावजूद, प्रवासी पक्षियों के प्रमुख ठिकाने के रूप में घटोरा वेटलैंड की राष्ट्रीय पहचान और दबदबा पूरी तरह बरकरार है। घटोरा वेटलैंड में जलीय प्रजातियों का एक जीवंत मिश्रण देखा गया है, जिसमें लालसर, धूसर कलहंस, सरपट्टी हंस, नार्दर्न पिनटेल, गैडवाल, गर्गनी और कॉमन टील शामिल हैं। इसके अलावा ब्लैक टेल्ड गॉडविट, स्पॉटेड रेडशैंक, ग्रीनशैंक और दुर्लभ शिकारी पक्षी 'हेन हैरियर' की मौजूदगी भी दर्ज की गई है।

भागलपुर जिले में पिछले चार वर्षों के दौरान पक्षियों की संख्या में लगातार और रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में यहां 7,544 पक्षी मिले थे, जो 2023 में बढ़कर करीब 9,000 और 2024 में 15,000 से अधिक हो गए।

अब 2025 में 23,268 का आंकड़ा यह साबित करता है कि चार साल में पक्षियों की संख्या तीन गुना से भी अधिक हो गई है। भागलपुर के जिला वन पदाधिकारी आशुतोष राज ने बताया कि गंगा से जुड़ी आर्द्रभूमियां और जलाशय पक्षियों को पर्याप्त भोजन और शांत वातावरण उपलब्ध कराते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित पक्षी गणना से जैव विविधता और पर्यावरण में आने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलती है। इन प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण स्थानीय और विदेशी दोनों पक्षियों के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है।

44 दिनों के लिए बंद हुआ बिहार का ये महत्वपूर्ण पुल

पश्चिम चंपारण, एजेंसी। बिहार के बेतिया से गोपालगंज या गोपालगंज से बेतिया आने-जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। गंडक नदी पर बने मंगलपुर-जादोपुर पुल को मरम्मत कार्य के चलते 44 दिनों के लिए पूरी तरह बंद किया गया है। ऐसे में आम यात्रियों के साथ-साथ कारोबारियों और किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब बेतिया से गोपालगंज या गोपालगंज से बेतिया आने-जाने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी।

दरअसल, मंगलपुर- जादोपुर पुल पर मरम्मत कार्य को लेकर यह फैसला लिया गया है। 11 नवंबर यानी आज से पुल पर मेगा ब्लॉक लागू हो गया है, जो 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान पुल के दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अब तक पुल पर केवल भारी वाहनों के परिचालन पर रोक थी, जबकि बाइक और छोटे वाहन गुजर रहे थे। लेकिन मरम्मत कार्य के दौरान छोटे-बड़े सभी वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है।

पुल बंद होने का सीधा असर बेतिया और आसपास के इलाकों से गोपालगंज जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। यात्रियों को अब वैकल्पिक रास्ते से सफर करना होगा। जिसकी दूरी लंबी हैं। इसके लिए बेतिया से खजुरिया होते हुए महम्मदपुर के रास्ते गोपालगंज जाना पड़ेगा। जिस कारण यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक दूरी तय करनी होगी। इससे न सिर्फ समय की बर्बादी होगी, बल्कि ईंधन पर भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।

इसी साल 23 मई को पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई थी। जांच के दौरान पुल के पांचवें पिलर के पास स्पैन में करीब पांच से सात इंच की दरार पाई गई थी। इसके बाद पुल की सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी।

बिहार के खेल भवनों में अब खेल संघ करा सकेंगे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण

पटना, एजेंसी। बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब जिलों में बने खेल भवनों का इस्तेमाल संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए कर सकेंगे।

इसके साथ ही अब जरूरत के अनुसार एक जिले में एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर भी खोले जा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर लिए गए इस फैसले से खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए जगह की समस्या से राहत मिलेगी और खिलाड़ियों को अपने जिले में ही अभ्यास का बेहतर अवसर मिल सकेगा।

इस फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 नवंबर को पाटलिपुत्र खेल



परिसर में आयोजित जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान की थी। उन्होंने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए जिलों के खेल भवनों को खेल संघों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करने की दिशा में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसी कड़ी में सोमवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल भवनों में संचालित किए जा सकने वाले इंडोर खेलों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, फेंसिंग, योग और वुशु खेल संघों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में खेल भवनों के बेहतर इस्तेमाल और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बैठक में खेल संघों के प्रतिनिधियों को बताया कि वे अपने खेल की जरूरत, खिलाड़ियों की संख्या और संबंधित क्षेत्र में खेल के विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के लिए एक या एक से अधिक जिलों के खेल भवनों का चयन कर सकते हैं। इन भवनों में प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि, खिलाड़ियों के चयन और उनके प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की व्यवस्था संबंधित खेल संघों को ही करनी होगी।

खेल प्रशिक्षण को लेकर एक और अहम बदलाव किया गया है। रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि खेलो इंडिया की नीति में हाल में हुए बदलाव के बाद अब किसी जिले में जरूरत के अनुसार एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खोले जा सकेंगे। इससे पहले प्रत्येक जिले में खेलों की आवश्यकता के अनुसार एक स्मॉल सेंटर खोलने की योजना थी। नई व्यवस्था से अलग-अलग खेलों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

''इन सेंटरों में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के चयन में संबंधित खेल संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं, चयनित प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए जरूरी खेल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की होगी।

डॉक्टरों ने दे दिया था जवाब, फिर भी नहीं मानी हार, बिहार के दिव्यांग शमीम की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की अनोखी कहानी

गयाजी, एजेंसी। 'मैं पैरों से दिव्यांग हूं, दौड़ नहीं सकता हूं। कुछ सालों पहले मेरी इसी स्थिति को देख कर माता पिता भी मायूस थे। माता पिता को लगता था कि जिंदगी के सफर में हम दौड़ेंगे कैसे? हर दिन यही सवाल उनके सामने थे , लेकिन एक दिन किस्मत बदली, जिन पैरों से दौड़ नहीं सकता था, आज उन्हीं पैरों ने दुनिया के सामने मुझे पहचान दिलाई है।' यह कहना है बिहार के गयाजी शहर के इस्लामगंज कटारी के रहने वाले 36 साल के मोहम्मद शमीम का।

मोहम्मद शमीम दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। उनका बायां पैर सबसे ज्यादा प्रभावित है और वो पूरी तरह से काम नहीं करता है। लेकिन आज एक पैर से वो सिलाई मशीन चला कर टेलरिंग स्किल में इतने माहिर हो चुके हैं कि लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं।

पिता बताते हैं कि वो गरीबी के बावजूद शमीम को हर बड़े अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे थे, लेकिन जब अंतिम बार एम्स के चिकित्सकों ने इनसे कहा कि अब इसी तरह शमीम जीवन बिताएगा, तब उन्होंने थक हार कर इलाज कराना तो बंद किया, लेकिन उनके सामने बेटे के रोजगार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई।

'शमीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। बस दसवीं तक पढ़ा हुआ है। जब इसके भविष्य के बारे में हमें चिंता हुई तब इसे कई जगहों पर काम पर लगाया, लेकिन हर



जगह मायूसी ही हाथ लगी। लोग एक सप्ताह के अंदर इसे ना सिर्फ बाहर कर देते थे बल्कि ताने भी मारते थे। जब कोई लंगड़ा कहता था तो सोचिए एक पिता पर क्या गुजरती होगी

शमीम ने अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स में अपनी अलग पहचान भी बनाई है। तीन बार भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय एबिलिंपिक्स में कर चुके हैं और चौथी बार के लिए वो तैयारी में भी लगे हैं। हालांकि एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाले मो शमीम का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने और वहां तक का सफर भी उनके लिए आसान नहीं था। सारी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हुए समाज के आम वर्ग के लिए वो एक उदाहरण स्वरूप हैं।

पूर्व पैरालंपिक खिलाड़ी मो हामिद अली बताते हैं कि मोहम्मद शमीम फ्रांस से लेकर दक्षिण कोरिया तक में आयोजित होने वाली एबिलिम्पिक्स में वो भाग ले चुके हैं। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम किया है। 2009 से शमीम ने अपने सफर की शुरुआत की थी।

दरअसल एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिता मुख्य रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयोजित होती है। यह एक वैश्विक व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता होती है और दुनिया भर के कई देशों में ओलंपिक और पैरालंपिक की तरह ही इसका आयोजन होता है। इसको 'दिव्यांगों की क्षमताओं का ओलंपिक' भी कहा जाता है।

दिव्यांगों के लिए एक पैरालंपिक होता है जिस में स्पोर्ट्स प्रतिभागी भाग लेते हैं। जबकि दूसरा एबिलिम्पिक्स होता है जिसमें कोई खेल कूद की तरह प्रतियोगिता नहीं होती है। बल्कि एक हुनर और कौशल प्रदर्शन का ये मंच होता है। इसमें पैरालंपिक की तरह ही कई देशों के खिलाड़ियों के बीच प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। इसमें लगभ 35 तरह के स्केल शामिल होते हैं। यह प्रतियोगिता भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। एबिलिम्पिक्स का आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता है।

एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिता में जीत हार का निर्णय पूरी तरह से व्यावसायिक योग्यता और निर्धारित अंकों के आधार पर किया जाता है। इस प्रतियोगिता में कुल 100 अंक दिए जाते हैं, जबकि इस प्रतियोगिता में हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग टाइमिंग होती है। कोर्ट पैंट सिलाई और अन्य फैशन डिजाइनिंग के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित होता है।

अंकों को कार्य की जटिलता के आधार पर अलग-अलग मानदंडों में विभाजित किया जाता है। इसमें कुल 6 जज होते हैं, जिनमें 5 जजों का पैनल दो अलग-अलग तरीकों से प्रतिभागियों के काम को मापता है। जबकि एक जज सभी 5 जजों के अंकों और सारी प्रक्रियाओं का आंकलन करता है।

किसी बाधा में अंतिम निर्णय लेने का हक छठे जज को होता है। यानी कि एक तरह से छठा जज क्रिकेट के थर्ड अंपायर की तरह काम करता है। इसमें स्केल, फिनिशिंग, तेजी , मशीनों को चलाने के स्मार्ट तरीके, टाइम मैनेजमेंट और फैंसी डिजाइन पर अंक दिए जाते हैं। जो जितने कम समय में बिना गलती किए हुए अच्छे ढंग से अपने टास्क को पूरा करता है उसे उतना ही नंबर दिया जाता है।

संक्षिप्त समाचार

अलीगढ़ होकर गुजरेंगी दो वंदे भारत त्योहार विशेष ट्रेन

अलीगढ़ , एजेंसी। दीपावली और छठ पर्व पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा और छठ स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इनमें दो वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें अलीगढ़ होकर गुजरेंगी। इससे बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार, नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल (02258) 11 नवंबर को नई दिल्ली से सुबह पांच बजे रवाना होगी। यह ट्रेन सुबह 6:28 बजे अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद 6:30 बजे रवाना होगी। पटना जंक्शन पर शाम 6:30 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 02257 पटना से 12 नवंबर को सुबह आठ बजे रवाना होकर शाम 6:53 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी। यहां दो मिनट रुकने के बाद 6:55 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। नई दिल्ली में रात 9:30 बजे पहुंचेगी। इसी तरह दूसरी वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल (02436) 13 नवंबर को नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे चलेगी और सुबह 10:21 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद 10:23 बजे रवाना होकर रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 02435 पटना से 14 नवंबर को सुबह आठ बजे चलकर शाम 6:53 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी और 6:55 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होगी।

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए कुबेरपुर में बनेगा डिपो, जमीन चिह्नित

आगरा, एजेंसी। शहर के ट्रैफिक को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कंपनी ने शहर में 100 ई-बसों के संचालन के लिए कुबेरपुर में जमीन चिह्नित की है। जमीन हस्तांतरित करने के लिए कंपनी ने जिला प्रशासन से संपर्क भी साध लिया है। जमीन ट्रांसफर होने के बाद नगर विकास विभाग वहां डिपो को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। दरअसल, जिले में 100 नई इलेक्ट्रिक (ई-बस) बसों के संचालन शुरू किया जाना है। इसके लिए अलग से डिपो की जरूरत है, जहां चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था हो सके। इसी क्रम में नगरीय परिवहन निदेशालय, लखनऊ के निर्देश पर आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर डिपो निर्माण के लिए चिह्नित भूमि को नगर विकास विभाग के नाम निशुल्क हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। एमडी ने बताया कि शहर में जीसीसी मोड पर ई-बसों को चलाए जाने की योजना प्रस्तावित है। इसी क्रम में एत्मादपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कुबेरपुर में स्थित कुल 1.4680 हेक्टेयर भूमि को डिपो निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया है। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि बंजर के रूप में दर्ज है और वर्तमान में रिक्त है। शासन की मंशा के अनुसार ई-बसों के निर्बाध संचालन और डिपो के मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चिह्नित भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के नाम पर होना अनिवार्य है। भूमि के हस्तांतरित होते ही डिपो का निर्माण कार्य गति पकड़ेगा, जिससे आगरावासियों को जल्द ही नई ई-बसें मिलेंगी।

भाजपा नेता की कार में ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग

आगरा, एजेंसी। दीपावली की रात आतिशबाजी के बीच यमुनापार में भाजपा नेता की स्कॉर्पियो को निशाना बनाकर आग लगा दी गई। आरोपी ने पहले पत्थर से कार का अगला शीशा तोड़ा, फिर अंदर और गाड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में स्कॉर्पियो धू-धूकर जलने लगी। शुरुआत में परिजनों को लगा कि आतिशबाजी की चिंगारी से कार में आग लगी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर जानबूझकर आग लगाने की वारदात सामने आई। एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर निवासी भाजपा नेता सौरभ ठाकुर सोमवार रात दीपावली पर ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज-2 स्थित पानी की टंकी के पास अपनी बुआ के घर गए थे। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो घर के बाहर खड़ी कर दी थी। देर रात करीब 1 बजे अचानक कार आग की लपटों से घिर गई। कार जलती देखकर परिजनों में खलबली मच गई। बाद में घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो एक युवक पत्थर से शीशा तोड़ता और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाता दिखाई दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से चला गया। पुलिस रंजिश समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। अभी पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भाजपा नेता की गाड़ी को निशाना बनाने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। - श्वेता वर्मा, एसीपी छत्ता

74 करोड़ का हुआ पटाखा कारोबार, पिछले साल से चार करोड़ अधिक

कानपुर , एजेंसी। भैयादूज के साथ बुधवार को पांच दिवसीय दीपोत्सव का समापन हो जाएगा। इस बार दिवाली ने पटाखा कारोबार को नई रौनक दी। शहर में पटाखों का कुल कारोबार 74 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 70 करोड़ रुपये था। यानी कारोबार में चार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि दुकानों की संख्या बढ़ने से थोक बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक रही और कई कारोबारियों का स्टॉक नहीं बिक पाया। बिठूर के सिंहपुर में इस बार थोक पटाखा बाजार में 80 लाइसेंस जारी किए गए थे। पिछले वर्ष यहां महज 30 से 32 दुकानें ही लगी थीं। इस बार अधिकतर लाइसेंसधारकों ने दुकानें लगाईं और अच्छा स्टॉक भी मंगाया। शहर के विभिन्न इलाकों में फुटकर पटाखों की दुकानें भी सजी थीं। बाजार में इस बार 800 फीट तक ऊंचाई पर जाकर फूटने वाले पटाखों के साथ 500 और 100 से 200 फीट तक जाने वाले 60 व 120 शॉट वाले पटाखे भी उपलब्ध रहे। अंब्रेला पैराशूट स्टाइल पटाखों की भी अच्छी मांग रही। अनार, फुलझड़ी, रॉकेट, सीको और चक्करगिन्नी खरीदारों की पसंद बने रहे। कारोबारियों के मुताबिक पटाखों के दाम पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक थे। आसमान में जाकर फूटने वाले पटाखों की मांग में 30 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

सुबह कोहरा और रात में बढ़ी ठंड, सात जिलों में 15 डिग्री के करीब पहुंचा पारा



लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में मौसम अब सर्दियों की ओर बढ़ रहा है। सुबह कोहरा और रात में गिरता तापमान ठंड बढ़ने का संकेत देने लगा है। मंगलवार को तराई, अवध और पूर्वी यूपी के कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। वहीं दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से राहत बनी रही।

मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से कोहरे में कमी आएगी। साथ ही फिलहाल अगले पांच दिन, दिन व रात के पारे में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह शाम और रात के मौसम में यूं ही नरमी बनी रहेगी।

उधर दीपावली के अगले दिन सोमवार सुबह पश्चिमी तराई, अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। कुछ स्थानों पर इसकी सघनता इतनी अधिक रही कि दृश्यता काफी कम हो गई। वाराणसी में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जबकि बरेली में यह महज 100 मीटर दर्ज की गई। राजधानी लखनऊ में भी सुबह दृश्यता घटकर 300 मीटर रह गई।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले पांच दिन बाद पछुआ हवा रफ्तार पकड़ेगी और इसके असर से ठंड में इजाफा होगा। अगले पांच दिनों तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई है।

सात जिलों में 15 डिग्री के आसपास पहुंचा रात का पारा

सोमवार और मंगलवार के बीच की रात प्रदेश के करीब सात जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हरदोई में पारा गिरकर 13.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ इटावा में सबसे ठंडा दिन रहा।

वंदे मातरम के उद्घोष से पंडाल गूंजा



वाराणसी , एजेंसी। मुस्तफाबाद गांव में मां काली पूजा महोत्सव के तहत रविवार रात बिरहा मुकाबले का आयोजन हुआ। श्री बजरंग दल मां काली पूजा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना और गायिका रजनीगंधा के बीच मुकाबला हुआ। दोनों कलाकारों ने वीर और भक्ति रस की प्रस्तुतियों से श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। ओमप्रकाश दीवाना ने उरी आतंकी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की घटनाओं को बिरहा के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने घायल सैनिक भानु सिंह और उनके बेटे सूरज की वीरता का भी वर्णन किया। उनकी प्रस्तुति के दौरान 'सरहद पार गोली भी बोली, वंदे मातरम' के उद्घोष से पंडाल गूंज उठा।

वहीं, रजनीगंधा ने जामवंत प्रसंग और भगवान श्रीराम के आदर्शों पर आधारित भक्ति गीत प्रस्तुत किए। उन्होंने लक्ष्मण के संस्कार, भक्ति और त्याग का वर्णन किया। दोनों कलाकारों की प्रस्तुतियों पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। सोमवार सुबह हवन-पूजन के साथ तीन दिवसीय मां काली पूजा महोत्सव का समापन हुआ। शाम को देवी गीतों और विदाई गीतों के बीच मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया गया।

लापरवाही के भंवर में फंसा बटेश्वर का पांटून पुल



आगरा, एजेंसी। बटेश्वर के लोक मेला का बुधवार को शुभारंभ होगा। मंदिर शृंखला को यमुना नदी के दूसरे छोर पर जोड़ने वाले पांटून पुल का निर्माण नहीं हो सका है। इससे श्रद्धालु और कछार में बसे गांवों के लोग परेशान हैं।

बटेश्वर और कल्यानपुर भरतार गांव के बीच यमुना नदी पर हर साल 15 अक्तूबर से पांटून पुल बन जाता था। 25 दिन बीतने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो सका है। इससे दोनों गांवों के अलावा बटेश्वर दर्शन, पूजन एवं स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। भरतार के ब्रजवीर सिंह, जगवीर सिंह ने बताया कि पुल का निर्माण न होने से खेतों की बुवाई के लिए खाद बीज भदरौली के रास्ते लाना पड़ रहा है। इसके लिए 25 से 30 किमी अतिरिक्त चलने को ग्रामीण मजबूर हैं। ग्रामीण और रिश्तेदार मोटरबोट के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। समय पर पुल का निर्माण न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई।

बटेश्वर में दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे शिकोहाबाद के विजय बहादुर, सिरसागंज के जगराम, जैतपुर के रामवीर, सुनील, हेमलता, रेखा आदि ने बताया कि स्नान पर्व पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर श्रद्धालु पुल पार कर नदी के दूसरे छोर पर आसानी डुबकी लगा लेते थे। पुल न बनने की वजह से नाव से नदी पार करना जोखिम भरा रहेगा। श्रद्धालुओं ने स्नान पर्व से पहले पुल का निर्माण कराए जाने की मांग की।दिवाली पर श्रमिक छुट्टी पर चले गए थे। एक-दो दिन में पांटून पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा।

दिवाली के धुएं की मार, लेडी लॉयल पहुंची गर्भवती महिलाएं



आगरा , एजेंसी। दिवाली के समय आतिशबाजी और धुएं से फैली प्रदूषित हवा का असर अब गर्भवती महिलाओं की सेहत पर दिख रहा है। वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत और एलर्जी की समस्या को लेकर महिलाएं में जिला महिला चिकित्सालय पहुंच रही हैं। प्रदूषित हवा और धुएं के इस गंभीर प्रकोप से गर्भ में पल रहे शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं।

लेडी लॉयल अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ममता किरण ने बताया कि प्रदूषण के इस दौर में हवा में ऑक्सीजन का स्तर कम और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके चलते गर्भवती महिलाओं में सांस फूलना, घबराहट और सीने में जकड़न जैसी दिक्कत महसूस हो सकती हैं। प्रदूषण से गर्भ में पल रहे बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे निमोनिया का खतरा, प्रीमेच्योर लेबर पेन (समय से पहले प्रसव पीड़ा), और समय से पूर्व डिलीवरी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं। समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. आशु ने भी महिलाओं को इस मौसम में खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गर्भवती महिलाओं को अत्याधिक बाहर निकलने से बचना चाहिए और पूरी सतर्कता रखनी चाहिए।

- पटाखों के धुएं और प्रदूषित हवा के कारण सांस लेने में परेशानी और अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। इसलिए जांच कराने अस्पताल आई हूं। काजल, धनौली

- नौवां महीना अभी लगा नहीं उससे पहले ही प्रसव पीड़ा हो रही है जिसके कारण अस्पताल में जांच के लिए आई। खुशी, सेवला

बरतें सावधानी

पटाखों के धुएं और अत्यधिक प्रदूषण वाले इलाकों में जाने से बचें।

घर से बाहर निकलते समय मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे।

सांस फूलने या घबराहट होने पर जल्द डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी नियमित जांच में किसी प्रकार की कोताही न बरतें।

गोवर्धन पूजा के दिन गंगाजल को तरसे 9 लाख लोग, 22 दिन तक बंद रही अपर गंगा कैनाल



आगरा, एजेंसी। गोवर्धन पूजा के दिन मंगलवार की सुबह शहर के 9 लाख से ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिला। जीवनी मंडी और सिकंदरा वाटरवर्क्स से जुड़े क्षेत्रों में गंगाजल नहीं पहुंच पाया। सिकंदरा का केवल एमबीबीआर प्लांट ही चलाया गया, जिसमें 72 एमएलडी यमुना जल की आपूर्ति आवास विकास, शाहगंज, केदार नगर क्षेत्र में हो पाई। बुलंदशहर के पालड़ा में अपर गंगा कैनाल के दिवाली पर शुरू होते ही इसमें शव बहकर आ गया, जिसे पालड़ा प्लांट के गेट बंद कर रोका गया। शव निकालने के कई घंटे बाद पालड़ा से आगरा के लिए आपूर्ति शुरू की गई।

जीवनी मंडी वाटरवर्क्स से केवल गंगाजल की आपूर्ति आधे शहर के लिए होती है। ताजगंज, फतेहाबाद रोड, छीपीटोला, बालूगंज, जीवनी मंडी, काला महल, पीपल मंडी, रावतपाड़ा, मंटोला समेत पुराने शहर के क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा के दिन सुबह आपूर्ति नहीं हुई। कई घरों में सुबह सूर्योदय से पहले स्याऊ का पूजन होता है, ऐसे में सुबह पानी न होने से उनके सामने संकट रहा। पड़ोसियों से अलसुबह सबमर्सिबल पंप चलवाकर उन्होंने पानी भरा।

इसी तरह सिकंदरा से 144 एमएलडी गंगाजल प्लांट बंद रहा। केवल 72 एमएलडी यमुना जल का शोधन ही एमबीबीआर प्लांट से किया जा सका, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में ही पानी पहुंचा। 75 फीसदी लोग पानी के लिए परेशान रहे।

बुलंद शहर के पालड़ा से आगरा को 140 और मथुरा को 10 क्यूसेक गंगाजल की आपूर्ति होती है। सिंचाई विभाग ने हरिद्वार में वार्षिक सफाई कार्यक्रम के कारण 16 अक्तूबर से 22 दिनों तक नहर बंद रखी, जिस वजह से केवल मध्य गंगा कैनाल से पालड़ा को गंगाजल दिया गया। दिवाली की रात अपर गंगा कैनाल को शुरू किया गया, लेकिन शव बहकर आ जाने से सिंचाई विभाग ने गेट बंद करा दिए। इस वजह से मंगलवार सुबह की जलापूर्ति ठप रही।

सूर्य उपासना के महापर्व से पहले अव्यवस्था का ग्रहण

कानपुर , एजेंसी। छठ महापर्व में महज तीन दिन शेष हैं लेकिन शहर के घाटों पर बदइंतजामी का अंधेरा पसरा है। कहीं नहरों में गंदगी बह रही है तो कहीं सिल्ट जमा है। पूजा की बेदियां गंदगी से घिरी हैं और रंगाई-पुताई तक नहीं हुई है। घाटों तक जाने वाले रास्ते भी बदहाल हैं। शाम होते ही कई जगह अंधेरा छा जाता है।

छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से होनी है। शहर में पूर्वांचल और बिहार की करीब आठ से साढ़े आठ लाख आबादी छठ महापर्व मनाती है। महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। शहर में कृत्रिम तालाबों, गंगा तटों और नहरों को मिलाकर 50 से 55 स्थानों पर पूजा होती है। सीटीआई नहर गंदगी से पटी है। पनकी, आवास विकास, कल्याणपुर, रविदासपुरम और बर्रा के घाटों पर भी सफाई अधूरी है। कई जगह रास्तों पर गिट्टी बिखरी है और रोशनी के इंतजाम नहीं हैं। पनकी छठ पूजा नहर से आवास विकास-1 की ओर जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। गणेश महोत्सव के दौरान कृत्रिम तालाबों में प्रतिमा विसर्जन के बाद उनकी सफाई भी नहीं कराई गई।

नहरों के किनारे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होने से श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ सकती है। नगर निगम की सुस्ती को लेकर भोजपुरी समाज ने नाराजगी जताई है। शास्त्रीनगर बड़ा और छोटा सेंट्रल पार्क, कमलानगर पार्क, जेपी पार्क विजयनगर, नमक फैक्टरी और तिलेश्वर मंदिर के पास कृत्रिम तालाब में पूजा होगी।

अरमापुर, पनकी, सीटीआई, साकेतनगर, आवास विकास, नौरैयाखेड़ा, रतनपुर, दबौली, अटल घाट, सरसैया घाट, मैस्कर घाट, गोलाघाट, सिद्धनाथ घाट और रविदासपुरम में नहर और नदी किनारे स्थित घाट पर पूजा होती है।

संदीप सिंह की सगाई में राज्यपाल

मुख्यमंत्री समेत दो लाख से अधिक मेहमानों के पहुंचने की तैयारी



अलीगढ़ , एजेंसी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरव सिंह की सगाई समारोह को यादगार बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। 14 नवंबर को तालानगरी में होने वाले इस समारोह में दो लाख से अधिक मेहमानों के शामिल होने की तैयारी है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना है।

प्रदेश की पूरी कैबिनेट के अलावा भाजपा के सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। वीवीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर यातायात और हवाई आवागमन तक की व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। समारोह के लिए तालानगरी में सेंट फिदेलिस स्कूल के बराबर स्थित 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल वाले मैदान को भव्य आयोजन स्थल का रूप दिया जा रहा है।

राजस्थानी शैली में बन रहा पंडाल : आयोजन स्थल को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि एक साथ बड़ी संख्या में मेहमानों की मौजूदगी के बावजूद व्यवस्थाएं सुचारु बनी रहें। मुजफ्फरनगर के एक बड़े डेकोरेटर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंडाल के इंटीरियर में राजस्थानी शैली की झलक देखने को मिलेगी। डेढ़ हजार से अधिक कारीगर तैयारियों में जुटे हैं।

तीन हेलीपैड तैयार, एयरपोर्ट पर भी वीवीआईपी इंतजाम : समारोह में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य विशिष्ट अतिथियों के संभावित आगमन को देखते हुए आयोजन स्थल पर तीन हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके साथ ही अलीगढ़ एयरपोर्ट पर भी वीवीआईपी विमानों और मेहमानों के आगमन को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार आयोजन स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग, मेहमानों के प्रवेश और निकास तथा यातायात प्रबंधन को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं।

स्वागत के लिए अलग-अलग दस्ते होंगे तैनात : समारोह में प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने को देखते हुए उनके स्वागत के लिए अलग-अलग दस्ते तैयार किए जा रहे हैं। अतिथियों के आगमन और उनकी अगवानी की जिम्मेदारियां भी अलग-अलग टीमों को दी जा रही हैं, ताकि समारोह के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। तालानगरी के अलावा राज्यमंत्री संदीप सिंह के मैरिस रोड स्थित आवास पर भी समारोह से जुड़ी तैयारियां की जा रही हैं।

दिल्ली में समारोह के लिए राष्ट्रपति, पीएम को दिया निमंत्रण : राज्यमंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरव सिंह के विवाह का मुख्य कार्यक्रम 27 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होगा। इसके लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजवीर सिंह राजू अपनी पत्नी एवं पूर्व विधायक प्रेमलता वर्मा, पुत्र संदीप सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को विवाह समारोह का निमंत्रण पत्र सौंपा। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी विवाह का निमंत्रण भेजा गया है। - वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अभी किसी का भी कोई अधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है लेकिन हमने अपनी ओर से सभी व्यवस्थाएं की हैं।

संक्षिप्त समाचार

कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में 29 वर्षीय युवक ने लगाई छलांग, तलाश जारी

नईदिल्ली, एजेंसी। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में 29 वर्षीय युवक के छलांग लगाने का



मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद से ही बचाव दल युवक की तलाश में जुटे हैं। अभी फिलहाल तलाश युवक का पता नहीं चल सका है। दक्षिण-पूर्वी जिले के उप मंडलीय वाईन राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सूचना मिलते ही संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया था। बचाव दल लगातार यमुना में युवक की तलाश कर रहे हैं। युवक की पहचान रंजीत के रूप में हुई है। उनके भाई से संपर्क किया गया है। युवक का पता चलने तक तलाश अभियान जारी रहेगा।

दिल्ली की अदालतों में 16 नवंबर को छठ की छुट्टी, हाईकोर्ट ने जारी किया नया शेड्यूल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अवकाश की घोषणा के बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली की अदालतों में भी छठ के अवसर पर अवकाश की घोषणा कर दी है। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सोमवार, 16 नवंबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ (निचली) सभी अदालतों में छठ पूजा के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। अधिसूचना में जहां 16 नवंबर की छुट्टी की घोषणा है वहीं उसमें साफ लिखा है कि सोमवार की जगह शनिवार को हाई कोर्ट खुला रहेगा। तीसरे शनिवार यानी 21 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट खुला रहेगा। वहीं अधीनस्थ अदालतें दिसंबर के दूसरे शनिवार को यानी 12 दिसंबर को खुली रहेंगी। 16 नवंबर के केस की सुनवाई 17 नवंबर को होगी नोटिफिकेशन के अनुसार, 16 नवंबर को जिन मामलों की सुनवाई होनी थी अब उन मामलों की सुनवाई 17 नवंबर को होगी। यह सुनवाई उस दिन पहले से सूचीबद्ध मामलों के अतिरिक्त होगी।

दिवाली पर दिल्लीवाले गटक गए 589 करोड़ की शराब

नई दिल्ली, एजेंसी। दीपावली पर रोशनी से संबंधित आइटम, मिठाइयों की खरीदारी के साथ दिल्ली में शराब की बिक्री भी खूब बढ़ी। त्योहार से पहले शराब की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रही।आबकारी विभाग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, दीपावली से पहले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली में करीब 589.17 करोड़ रुपये की शराब का कारोबार हुआ। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 70.20 करोड़ रुपये अधिक है। इस तरह शराब की बिक्री में 13.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

दिल्ली के नांगली विहार में दर्दनाक हादसा, 4 साल का बच्चा खुले सीवर में गिरा

नईदिल्ली, एजेंसी। रणहौला थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक चार साल का बच्चा खुले सीवर में गिर गया। हादसा खेड़ी बाबा पुल के पास गंदा नाला के किनारे सर्विस रोड पर हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बच्चे को सीवर से बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस के अनुसार, चार वर्षीय बच्चा अपनी मां के साथ मोहन गार्डन स्थित सोम बाजार वाली गली से दास गार्डन पार्क आया था। इसी दौरान बच्चा शौच के लिए नाले की तरफ जाने लगा। वहां सर्विस रोड के किनारे बने सीवर के मैनहोल में वह गिर गया। घटना की सूचना मंगलवार दोपहर करीब 3:21 बजे रणहौला थाने को मिली। पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर विवाद, हिंदू सेना ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र; सम्मान वापस लेने की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। सपा के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिए गए पद्म विभूषण सम्मान को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। हिंदू सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर दिवंगत नेता का पद्म विभूषण सम्मान तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। यह मांग ऐसे समय है जब सपा मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपरिवार 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने का ऐलान किया है। इस दौरे से पहले उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में अयोध्या में भक्तों की संख्या में कमी और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का जिक्र कर कहा है कि सपा सरकार आने पर पारदर्शी व्यवस्था से विश्वास बहाल किया जाएगा और अयोध्या को बाहरी ठेकेदारों से मुक्त कराया जाएगा। इसके पूर्व दान चोरी का मामला भी उन्होंने जोर शोर से उठाकर केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारों को घेरने की कोशिश की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में कहा कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केवल उन्हीं विभूतियों को दिए जाने चाहिए जिनका जीवन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक



समरसता और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रति समर्पित रहा हो। संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 1990 के अयोध्या गोलीकांड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

ज्ञापन में क्या लिखा है?: ज्ञापन के अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान निर्दोष और शांतिपूर्ण कारसेवकों पर तत्कालीन सरकार के आदेश पर हुई पुलिस फायरिंग एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन था। इसके साथ ही, पत्र में मुलायम सिंह यादव पर अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान श्रीराम मंदिर निर्माण के विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति करने के भी आरोप लगाए गए हैं।

वैसे, यह विवाद नया नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जब मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई थी, तब से ही इस निर्णय को हिंदू संगठनों तथा मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की ओर से आलोचना देखने को मिली थीं।

एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने इसे 'नेताजी' के कद के मुकाबले छोटा सम्मान बताते हुए भारत रत्न देने की मांग की थी, वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कई संगठनों और विपक्षी नेताओं ने 1990 की घटनाओं का हवाला देते हुए इस फैसले का कड़ा विरोध किया था।

शाहदरा डीसीपी ऑफिस का बदला पता, भोलानाथ नगर से थाने में हुआ शिफ्ट; एक ही छत के नीचे मिलेंगे 3 बड़े अफसर

नईदिल्ली, एजेंसी। शाहदरा थाने में 24 अक्टूबर को वकील और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हुआ था। जिसके बाद गांधी नगर के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। वकीलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जिसके बाद एसीपी को नौकरी से निलंबित कर दिया था। मंगलवार को उसी थाने में दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार पहुंचे। वजह विवाद नहीं थी। शाहदरा थाने से ही अब शाहदरा डीसीपी कार्यालय चलेगा। पुलिस आयुक्त ने नए डीसीपी आफिस का उद्घाटन किया। शाहदरा का डीसीपी कार्यालय भोलानाथ नगर क्षेत्र में चलता था। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ने डीसीपी आफिस के भवन को जर्जर घोषित कर दिया था। जिसके बाद डीसीपी ऑफिस को भोलानाथ नगर से शाहदरा थाने की पहली मंजिल पर स्थानांतरित किया गया है। शाहदरा थाने की तीन मंजिला बिल्डिंग में डीसीपी, एसीपी कार्यालय और साइबर थाना चलेगा।



दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का कहर, अस्पतालों में श्वास रोगियों की भीड़ बढ़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। दीपावली के बाद दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव ने अब अस्पतालों में श्वास और नेत्र संबंधी मरीजों की संख्या को बढ़ा दिया है। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में श्वास संबंधी समस्याओं की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में करीब 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। पूर्वी, पश्चिमी, बाहरी और दक्षिणी दिल्ली के अस्पतालों में भी प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मरीज पहुंच रहे हैं। सांस लेने में परेशानी, खांसी, अस्थमा, आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायतें बढ़ रही हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इसका अधिक असर दिखाई दे रहा है।

पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर स्थित दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में प्रदूषण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर इमरजेंसी और ओपीडी में करीब 200 मरीज पहुंच चुके हैं। इनमें सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, आंखों में तेज जलन और एलर्जी की शिकायत वाले मरीज शामिल हैं। अस्पताल पहुंचने वालों में बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों की संख्या अधिक है।

बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में श्वास और नेत्र संबंधी समस्याओं को लेकर करीब 200 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें शामिल अस्पताल में पहुंच रहे बच्चों में ज्यादातर आंखों में जलन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने बताया कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में सांस संबंधी समस्याओं को लेकर प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। स्वामी दयानंद सरकारी अस्पताल के बाल रोग चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रदूषण से बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल में पहुंच रहे बच्चों में ज्यादातर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के कारण ओपीडी में मरीजों की संख्या कम रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है।

एमसीडी राजस्व बढ़ाने के लिए एआई का सहारा, विज्ञापन स्थलों की होगी डिजिटल मैपिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। 16 हजार करोड़ का कर्जा झेल रहे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अब अपना राजस्व बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद लेगा। इसकी शुरुआत विज्ञापन विभाग से होगी। जहां पर सभी आउटडोर विज्ञापन स्थलों की डिजिटल मैपिंग होगी।

इसके तहत होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क और स्ट्रीट फर्नीचर समेत विज्ञापन से जुड़ी सभी परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकार्ड तैयार किया जाएगा। इससे अवैध विज्ञापनों की पहचान करने के साथ उन स्थानों का भी पता लगाया जा सकेगा, जहां विज्ञापन के जरिये अधिक कमाई की संभावना है।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्ताव तैयार...

एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एक निजी एजेंसी के साथ 180 दिन के पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत निजी एजेंसी अपने खर्च पर विज्ञापन स्थलों का सर्वे, जियो-टैगिंग और जीआईएस आधारित मैपिंग करेगी।

इस परियोजना पर निगम को कोई वित्तीय खर्च नहीं करना होगा। प्रस्ताव को स्थायी समिति के माध्यम से निगम की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

सत्या शर्मा ने कहा कि निगम के पास राजस्व अर्जित करने के कई संसाधन हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तकनीक की मदद से विज्ञापन परिसंपत्तियों की



वास्तविक स्थिति और उनकी व्यावसायिक क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। इससे राजस्व के नुकसान को रोकने और विज्ञापन प्रबंधन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत एजेंसी अपने एआई आधारित विजुअल लोड इंडेक्स (वीएलआई) टूल का इस्तेमाल करेगी। यह टूल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों की संख्या, दृश्यता और उनसे होने वाली दृश्य अव्यवस्था का विश्लेषण करेगा।

इसके आधार पर ऐसे विज्ञापन कॉरिडोर की पहचान होगी, जहां व्यावसायिक संभावनाएं अधिक हैं। इससे विज्ञापन स्थलों की नीलामी, मूल्यांकन और टेंडर प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निगम अधिकारियों के अनुसार निजी एजेंसी 360 डिग्री वर्चुअल सर्वे के जरिये प्रत्येक विज्ञापन स्थल की तस्वीरें, लोकेशन, आकार, रोशनी और नियमों के अनुपालन की जानकारी जुटाएगी।

ब्रिटेन में एयरबेस उड़ाने की थी साजिश, ईरान समर्थित नेटवर्क के तीन लोगों पर शिकंजा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अभियोजकों ने यूरोप में हमलों और अमेरिका में हिंसक वारदातों की साजिश रचने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामले दर्ज किए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, यह अभियान ईरान समर्थित था। इसमें ब्रिटेन के एक सैन्य एयरबेस पर हमले की नाकाम कोशिश भी शामिल थी, जहां उस समय अमेरिकी सैन्यकर्मी और विमान मौजूद थे।

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में आठ आरोपों वाली एक संशोधित अभियोग-पत्र (सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट) दाखिल की गई है। इसमें मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल-सादी (ईरानी-इराकी दोहरी नागरिकता), ईरानी नागरिक मोहसेन मोहाजेरी और इराकी नागरिक मोहम्मद अली अल-हसानी को आरोपी बनाया गया है।

क्या है आरोप

इन लोगों पर ईरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (आईआरजीसी) और 'कताइब हिजबुल्लाह' को समर्थन देने का आरोप है। अमेरिका ने इन दोनों संगठनों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अभियोजकों के अनुसार, यह नेटवर्क लगभग 20 हमलों और हमलों की कोशिशों से जुड़ा है।

ब्रिटिश एयरबेस ब्लॉक फेयरफोर्ड को बनाया था निशाना: अभियोजकों के मुताबिक, इस कथित साजिश का सबसे हालिया निशाना ब्रिटेन का ब्लॉक फेयरफोर्ड एयरबेस था। सितंबर में हमले की कोशिश के समय इस एयरबेस पर अमेरिकी विमान और सैन्यकर्मी तैनात थे। आरोपपत्र के अनुसार, अल-हसानी ने विदेश में रहते हुए ब्रिटेन में मौजूद अपने सहयोगियों की मदद से हमले की योजना तैयार की थी। उस समय मोहाजेरी भी ईरान में था, जबकि अल-सादी पहले से ही आतंकवाद से जुड़े एक अन्य मामले में न्यूयॉर्क की संघीय हिरासत में बंद था। अभियोजकों का दावा है कि जेल में होने के बावजूद अल-सादी ने इराक में अपने रिश्तेदारों से फोन पर बातचीत के जरिए सहयोगियों तक गुप्त संदेश पहुंचाए।

अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक, हमले की तैयारियां अगस्त में शुरू हुई थीं। आरोपियों के सहयोगियों ने एयरबेस की निगरानी और रेकी की। इसके अलावा वैन और ईंधन के ड्रम जुटाए गए। रासायनिक ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल पर जानकारी जुटाई गई और छर्रे के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले धातु के सामान भी हासिल किए गए। अभियोजकों ने बताया कि वैन पर ऐसे निशान लगाए गए थे, जिससे वे ईंधन की आपूर्ति करने वाली या स्विमिंग पूल से जुड़ी कंपनियों की गाड़ियां दिखाई दें। आरोपपत्र में यूरोप के यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कथित श्रृंखला का भी जिक्र है। अभियोजकों का कहना है कि आरोपी 'हरकत अशाब अल-यामिन अल-इस्लामिया' नाम के एक समूह के जरिए काम कर रहे थे। इसे ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों का मुखौटा संगठन बताया गया है।

इस समूह ने यूरोप में 18 हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इनमें से सात हमले ब्रिटेन में हुए थे। इन घटनाओं में आगजनी, विस्फोटक हमले और लंदन में दो यहूदी लोगों पर चाकू से किया गया जानलेवा हमला शामिल था। इस हमले में एक व्यक्ति की जान बाल-बाल बची थी। वह ब्रिटिश और अमेरिकी, दोनों देशों की नागरिकता रखता था। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से दाखिल आरोपपत्र में कई गंभीर आरोप शामिल हैं। इनमें अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित समूहों को भौतिक सहायता मुहैया कराने की साजिश, आतंकवाद के वित्तपोषण और सार्वजनिक स्थान पर बम विस्फोट करने की साजिश शामिल हैं। मामले की जांच के आधार पर अभियोजकों ने तीनों आरोपियों को कथित ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा बताया है। हालांकि, ये सभी आरोप हैं और अदालत में अभी इनकी पुष्टि होनी बाकी है।

एसयूवी कार की टक्कर से लॉस एंजिलिस में तीन की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजिलिस में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां नॉर्थ हॉलीवुड में मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर चल रहे लोगों को एक तेज रफ्तार सफेद एसयूवी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। लॉस एंजिलिस अग्निशमन विभाग (एलएएफडी) ने इसकी जानकारी दी।

लॉस एंजिलिस पुलिस विभाग (एलएपीडी) के मुताबिक, व्यस्त चौराहे पर शाम करीब छह बजे से ठीक पहले एक सफेद एसयूवी ने कम से कम पांच लोगों को टक्कर मारी। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें वाहन का चालक भी शामिल है। फिलहाल अभी तक हादसे की वजह सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। मंगलवार रात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलएपीडी के कैप्टन वार्नर कैस्टिलो ने कहा, 'हमें नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया था या दुर्घटनावश हुआ।' कैस्टिलो के मुताबिक, एसयूवी चालक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। उसकी उम्र 60 साल के आसपास है। अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए उसकी चिकित्सकीय जांच शुरू की है कि कहीं वह नशे के प्रभाव में तो वाहन नहीं चला रहा था। लॉस एंजिलिस की मेयर करेन बास ने बताया कि हादसे के शिकार लोगों में सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेता और राहगीर शामिल हैं। उन्होंने



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया। मेयर ने लिखा, 'इस हादसे से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के लिए मेरा दिल दुखी है।' वहीं, एलएपीडी के प्रमुख जिम मैकडॉनेल ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच लंबी चलेगी, लेकिन इसे बेहद सावधानी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

चक शूमर ने ट्रंप को घेरा, कहा- जेन्सेन हुआंग पर कार्रवाई के बजाय लिया 234 करोड़ रुपये का चंदा

वॉशिंगटन, एजेंसी। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग के कथित तौर पर चीनी जासूस से संबंधों को लेकर अमेरिका में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप को एक साल से अधिक समय पहले हुआंग के एक कथित चीनी जासूस के साथ संबंधों की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप को एनवीडिया के सीईओ और कथित चीनी जासूस के संबंधों के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।

शूमर ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने इसके बजाय हुआंग को बीजिंग की यात्रा



पर साथ ले गए, चीन को अमेरिकी एआई चिप्स तक पहुंच देने की उनकी सलाह मानी और एनवीडिया से 25 मिलियन डॉलर का चंदा स्वीकार किया। उन्होंने व्हाइट हाउस से तत्काल जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में ट्रंप प्रशासन की कथित नाकामी पर तुरंत जवाब मिलना चाहिए। शूमर का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जेन्सेन हुआंग का सार्वजनिक रूप से बचाव किए जाने के कुछ समय बाद आया है। ट्रंप ने हुआंग को शानदार और उच्च गुणवत्ता वाला व्यक्ति बताया था। उन्होंने एनवीडिया की ओर से विकसित ब्लैकवेल चिप की भी तारीफ की थी। हालांकि, ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इस पूरे विवाद से हुआंग और उनका परिवार काफी परेशानी झेल रहा है।

इस बीच एनवीडिया के बोर्ड ने मामले की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक, बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पूर्व कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जून एच. किम और उनकी कानूनी फर्म वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी ने कहा कि यह विस्तृत और स्वतंत्र जांच होगी। बोर्ड ने इससे पहले रविवार को भी जांच की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने भी ट्रंप प्रशासन की निर्यात नीति पर सवाल उठाए हैं। रोड आइलैंड के गैब अमो, न्यूयॉर्क के ग्रेगरी डब्ल्यू. मीक्स और कैलिफोर्निया की सिडनी कमलागर-डोव ने वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक से उन्नत एआई कंप्यूटर चिप्स के निर्यात की अनुमति से जुड़े सवालों का जवाब मांगा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सांसदों ने कहा कि वाणिज्य विभाग ने चीन से जुड़े संस्थानों, सैन्य ठेकेदारों और प्रतिबंधित कंपनियों को उन्नत एआई हार्डवेयर भेजने की मंजूरी दी थी। सांसदों ने अपने पत्र में लिखा कि अमेरिका की एआई क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता की रक्षा करने का दावा करते हुए उसकी सबसे उन्नत तकनीक किसी रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी तक पहुंचने देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कॉरपोरेट बिक्री के लक्ष्यों से ऊपर होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर मुख्यालय वाली डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी एलिस हुआंग को चीनी खुफिया एजेंसी ने अपने साथ जोड़ा था। मेगास्पीड ने एनवीडिया के हार्डवेयर खरीदे और दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर स्थापित किए। इन केंद्रों के जरिए अलीबाबा समेत मुख्यभूमि चीन की कंपनियों को सेवाएं दी जाती थीं।

फ्रिज नहीं संभलते, देश की समस्याएं क्या संभालोगे': ईरान का फ्रांस पर तंज; होर्मुज में अमेरिका को भी ललकारा

तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका पर होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना के कमांडर ने कहा कि अमेरिकी सेना खुद इस रणनीतिक समुद्री रास्ते के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही, लेकिन इसे खुला बताकर तेल टैंकरों को खतरे में भेज रही है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, कमांडर ने आरोप लगाया कि अमेरिका बेबस तेल टैंकरों को 'आग की दीवार' में धकेल रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बना हुआ है। अमेरिका के सामने ईरान ने रखीं सात शर्तें, ट्रंप ने क्या कहा इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए सात शर्तें रखी थीं। मानकर पश्चिम एशिया में नए समीकरण को स्वीकार करना चाहिए। इन शर्तों में सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म करना, होर्मुज के आसपास अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, समुद्री रास्ते को फिर खोलना, आर्थिक प्रतिबंध हटाना, विदेशों में जमा ईरान की संपत्तियां लौटाना और ईरान के आंतरिक मामलों में दखल बंद करना शामिल है।

संपादकीय | अग्निपथ योजना में बदलाव की चुनौती

अग्निपथ योजना में जबरदस्त परिवर्तन कर दिया गया है। भारतीय सेना के तीनों अंगों और कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। जिन अग्निवीरों को अपने 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद सेना को अलविदा कहना था, उनकी सेवा अवधि में अतिरिक्त 2 साल की वृद्धि की गई है, इसके बाद उन्हें अवसर दिया जाएगा कि वह सशस्त्र बलों में नियमित सैनिक बने रहना चाहते हैं या नहीं। इस संशोधित व्यवस्था में 4 वर्ष के प्रारंभिक कार्यकाल के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने के वर्तमान प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन शेष 75 प्रतिशत, जिन्हें 4 साल की सेवा के बाद सेना छोड़नी थी, को 2 बरस का एक्सटेंशन ऑफर किया गया है और इसके उपरांत उन पर नियमित कैडर के रूप में विचार किया जा सकता है। बशर्ते वह इसके लिए स्वयं इच्छुक हों और चयन पैमाने पर खरे उतरते हों। जो अग्निवीर दूसरी नियुक्ति अवधि के विकल्प का चयन करेंगे, उनके लिए सरकार ने अधिक पारिश्रमिक व बढ़ा हुआ सेवा निधि पैकेज (4 वर्ष पूर्ण करने पर अग्निवीरों को दिया जाने वाला एकमुश्त आर्थिक लाभ) को भी मंजूरी दी है। लेकिन नियमित प्रवेश पर उन्हें 25 प्रतिशत रिटेंशन प्रावधान के तहत सीधे नियमित कैडर के तौर पर भर्ती होने वालों की तुलना में एक रैंक नीचे रखा जाएगा। जब 2014-15 में वन रैंक, वन-पेंशन योजना लागू की गई, तो उसके बाद सैन्य वेतन व पेंशन पर खर्च आसमान छूने लगा, फलस्वरूप वार्षिक रक्षा बजट का आधे से अधिक इसी मद में जाने लगा। इस स्थिति को बरकरार रखना संभव न था। सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश,



उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व पंजाब (जिनमें एक वर्ष के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं) में युवा भारतीयों के लिए सेना में स्थायी नौकरी पारिवारिक परंपरा भी है और सामाजिक गति का अवसर भी। इसलिए अग्निपथ का पहला प्रयास यह होना चाहिए था कि जिन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 4 साल के बाद सेना छोड़नी थी, उनके लिए उनके प्रोफाइल के अनुसार अच्छे नागरिक जॉब की व्यवस्था होती। लेकिन ऐसे जॉब्स उपलब्ध न हो सके। दूसरा यह कि सेना के भीतर भी चिंताएं थीं कि मात्र 4 साल के बाद बड़ी तादाद में अग्निवीरों को निकालना व्यवधान डालने वाला होगा, क्योंकि सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने में बहुत समय लगता है। तीसरा यह चिंताएं भी थीं कि सेना छोड़ने वाले प्रशिक्षित अग्निवीरों का दुरुपयोग कहीं असामाजिक समूह या भाड़े के सिपाहियों के रूप में न किया जाने लगे। 18,000 अग्निवीरों की पहला बैच अपनी कार्य-अवधि के 4 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। सशस्त्र बलों ने उनके प्रदर्शन, कौशल, फिजिकल फिटनेस, लगन व ऑपरेशनल योगदान का विस्तृत मूल्यांकन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि यह मॉडल तीनों सेवाओं की संगठनात्मक जरूरतों की पर्याप्त पूर्ति करता है या नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस। राजा का कहना है कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य कभी यह नहीं था कि उसमें परिवर्तन किए ही नहीं जाएंगे और सशस्त्र बल इस बात के लिए समर्पित थे कि इसे लागू करने की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा अग्निवीरों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया जाता रहेगा। उनके अनुसार, आर्मी, नेवी व एयरफोर्स में केंद्रीकृत डाटाबेस रखने, अग्निवीरों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए, उद्देश्यपूर्ण पैमानों पर वार्षिक मूल्यांकन के साथ तीनों सेवाओं से जो मूल्यांकन व फीडबैक मिले, उनके आधार पर सशस्त्र बलों ने उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों की कार्य-अवधि में अतिरिक्त 2 वर्ष की वृद्धि की सिफारिश की जिन्हें नियमित कैडर के लिए चुना नहीं गया था।

अग्निपथ योजना में जो परिवर्तन किए गए हैं उनका क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है? जो अग्निवीर 4 साल के बाद सेना से निकल जाते, उन्हें 2 वर्ष अतिरिक्त काम करने का अवसर मिल गया है। इसके बाद भी अगर वह इच्छुक होंगे और पैमाने पर खरे उतरेंगे तो उन्हें सेना में स्थायी तौर पर बने रहने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन एक रैंक कम पर। इसलिए उन्हें सेवा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले घोषणा की गई थी।

लगातार चर्चा में जंगलराज, पर्यावरण की सिसकती आवाज

चंद्रमोहन द्विवेदी

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, विपक्ष हमेशा सरकार पर जंगलराज चलाने प का आरोप लगाता है, जबकि सरकार और प्रशासन आपसी मिलीभगत से जंगल कटवाते हैं, ताकि उद्योगों को जमीन मिल सके। महाराष्ट्र में जल विद्युत के लिए नाशिक के समीप बनाए जाने वाले टोरेंट प्रकल्प के खिलाफ पर्यावरण समर्थक आंदोलन की करंट फैल रही है। वृक्षों की कटाई कर प्रशासन साबित करना चाहता है कि वह न जंगल चाहता है, न जंगलराज! वह विकास पर जोर दे रहा है।' हमने कहा, 'जंगल कट भी जाएं तो भी राजनीति में जंगलराज का आरोप लगता ही रहेगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शहरी क्षेत्रों में भी रैली करके बिहार के चुनाव के समय कहा था कि राज्य को लालटेन युग और जंगलराज से बाहर लाना है।' पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, राजनीति में जंगलराज शब्द इतना चल पड़ा है कि हमें फिल्म 'जंगली' की याद आ रही है। लोग छुट्टी मिलने पर सीमेंट-कंक्रीट की इमारतों से दूर जाकर जंगल में मंगल मनाने का प्लान बनाते हैं। वह मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली और कूनो यूपी में जिम कार्बेट तथा महाराष्ट्र में ताड़ोबा जाना पसंद करते हैं। जंगल में भरपूर ऑक्सीजन रहती है। आपको शहर के प्रदूषण से बचना है, तो जंगल चले जाइए। प्राचीन काल में ऋषि-मुनि जंगल जाकर आश्रम बनाते और तपस्या किया करते थे।' हमने कहा, 'अब वन क्षेत्र में बिना परमिशन कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जंगल सरकारी हो गए हैं। आपको जंगल से ज्यादा प्रेम है तो घर बैठे रुडयार्ड किपलिंग की किताब 'जंगल बुक' पढ़ लीजिए या उस पर बनी एनिमेशन फिल्म 'मोगली' देख लीजिए। उसमें जंगल में भेड़ियों द्वारा पाले गए साहसी बच्चे मोगली, उसके हितैषी भालू बघीरा और शेरखान नामक बाघ की भूमिका है।' 'मोगली' फिल्म में गुलजार की लिखी पंक्तियां हर किसी की जुबान पर चढ़ गई थीं- 'जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है।' पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, प्रथम प्रधानमंत्री पं. नेहरू भी जंगल से लगाव रखते थे। उन्होंने अपनी डायरी में अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रास्ट की लाइन लिख रखी थी- 'वु आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टु कीप एंड माइल्स टु गो बिफोर आई स्लीप।' इसका अर्थ था जंगल घने और लुभावने हैं मगर मुझे वादे निभाने हैं और अंतिम नींद आने से पहले मुझे मीलों चलते जाना है!'



आज का कार्टून



विकास की वेदी पर बलि चढ़ती प्रकृति...

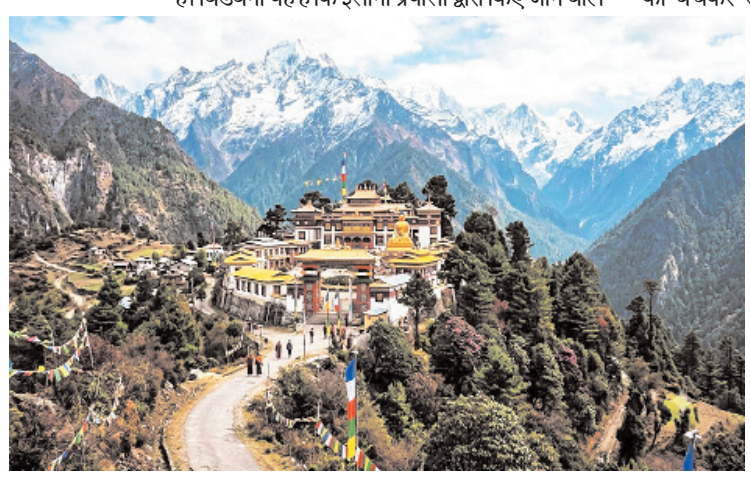
अशोक भाटिया

> 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को मंजूरी मिलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक नीतियों की एक बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन एक लाख पेड़ों की यह सामूहिक बलि इस जीत पर पर्यावरण की ओर से एक गहरा दाग भी है। जब हम एक लाख पेड़ काटते हैं, तो हम केवल लकड़ी का नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम हिमालय की संवेदनशील और दरकती पहाड़ियों की जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं, जिससे भविष्य में विनाशकारी भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और बड़े पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विकास और पर्यावरण के इस अंतहीन टकराव में अब हमें पुराने प्रशासनिक तौर-तरीकों से हटकर सोचने की सख्त जरूरत है। यदि इन पेड़ों को काटना एक अपरिहार्य तकनीकी मजबूरी है, तो इसके हर्जाने के तहत होने वाले वनीकरण को महज कागजी खानापूर्ति या दूसरे राज्यों में पेड़ लगाने की औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश केशी योमी और सियांग जिलों में सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति द्वारा प्राथमिक मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही इस परियोजना के लिए लगभग 470 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा, जिसके कारण इस अति-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र से एक लाख से अधिक हरे-भरे पेड़ों को काट दिया जाएगा। यह खबर औद्योगिक और ढांचागत विकास के मोर्चे पर जितनी सकारात्मक लगती है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उतनी ही भयावह है। पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, अपने सघन वर्षावनों और दुर्लभ जैव-विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में विकास के नाम पर एक लाख से अधिक जीवित वृक्षों की सामूहिक बलि देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह प्राकृतिक तबाही वाकई अपरिहार्य थी? क्या इस अभूतपूर्व नुकसान की भरपाई संभव है? और इस विनाश के बदले अरुणाचल प्रदेश तथा वहां के मूल निवासियों को वास्तव में क्या हासिल होने वाला है?

गौरतलब है कि बिजली घर, सुरंगें और भारी मशीनरी स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़े भूभाग की जरूरत है। इस विवाद में सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को उजाड़े बिना बांध का निर्माण संभव नहीं था? जलविद्युत परियोजनाओं की तकनीकी रूपरेखा पूरी तरह से नदियों के प्रवाह और पानी के विशाल संचय पर टिकी होती है। नायिंग परियोजना के लिए विशालकाय बांधजिस क्षेत्र में यह बांध प्रस्तावित है, वह उच्च संरक्षण मूल्य वाले घने जंगलों के अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग और जलविज्ञान के नियमों के मुताबिक, जब बांध के जरिए नदी के पानी को रोका जाता है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इस डूब क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ों और वनस्पतियों को पहले ही काट देना तकनीकी और सुरक्षा कारणों से जरूरी माना जाता है। यदि इन पेड़ों को बिना काटे वैसे ही पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए, तो पानी के भीतर वे सड़ने लगते हैं। इस सड़न से बड़े पैमाने पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है, जो पानी की गुणवत्ता को नष्ट कर पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देती हैं। यही वजह है कि जलाशय की जलधारण क्षमता बनाए रखने के लिए इन एक लाख पेड़ों को हटाना सरकारी ब्लूप्रिंट में एक व्यावहारिक विवशता बन जाता है।

जब हम एक लाख पेड़ काटने की बात करते हैं, तो प्रशासनिक फाइलों पर यह केवल एक निर्जीव संख्या की तरह दिखता है, लेकिन प्रकृति के विज्ञान में यह सदियों की अनवरत तपस्या का अंत है। इंसानी हाथों द्वारा लगाए जाने वाले कृत्रिम बागानों और प्राकृतिक वनों के बीच एक ऐसा अंतर होता है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। एक सामान्य पौधा लगाने के बाद उसे एक परिपक्व वृक्ष बनने में भले ही 15 से 20 वर्ष का समय लगता हो, लेकिन जब हम एक वास्तविक जंगल की बात करते हैं, तो वह केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जटिल और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अरुणाचल प्रदेश के ये जंगल अत्यधिक घने वन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें सदियों पुराने विशालकाय ओक, पाइन और देवदार के वृक्ष शामिल हैं। इस तरह के एक समृद्ध वर्षावन को पूरी तरह से अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप में लौटने के लिए कम से कम 80 से 150 वर्ष का लंबा वक्त लगता है। इन प्राकृतिक वनों में कई स्तरों पर वनस्पतियां, मिट्टी की सूक्ष्म जैविक संरचना, कवक और स्थानीय जीव-जंतुओं का एक पूरा संसार विकसित होता है। विडंबना यह है कि इंसानी प्रयासों द्वारा किए जाने वाले



प्रतिपूरक वनीकरण में लगाए गए पौधों में से केवल 20 से 25 प्रतिशत ही जीवित रह पाते हैं। इसलिए कोई भी कृत्रिम रोपण कभी भी उस प्राकृतिक जैव-विविधता का विकल्प नहीं बन सकता जो प्रकृति ने सदियों के क्रमिक विकास से तैयार की है।

भारतीय वन कानूनों के तहत, जब भी किसी विकास परियोजना के लिए वन भूमि का डायवर्जन किया जाता है, तो निर्माण एजेंसी से 'प्रतिपूरक वनीकरण' के तहत भारी आर्थिक हर्जाना वसूला जाता है। नायिंग परियोजना के लिए भी समिति ने सख्त शर्तें लगाई हैं, जिसके तहत काटे गए पेड़ों की संख्या से दोगुनी संख्या में नए पेड़ लगाने और नष्ट हुए वन्यजीव आवासों के पुनरुद्धार के लिए व्यापक योजना का खर्च उठाना होगा। परंतु, इस हर्जाने की नीति में एक बहुत बड़ी भौगोलिक विसंगति हमेशा से मौजूद रही है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग पहले से ही सघन वनों से ढका हुआ है, जिसके कारण राज्य के भीतर वनीकरण के लिए अतिरिक्त गैर-वन भूमि मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसी वजह से पूर्व की कई परियोजनाओं के अनुभवों को देखें, तो अरुणाचल में काटे जाने वाले वनों का हर्जाना और नया वनीकरण मध्य प्रदेश या अन्य मैदानी राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर दूर खाली पड़ी भूमि पर करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। यह प्रक्रिया कानूनी कागजों पर भले ही हर्जाना मान ली जाए, लेकिन पारिस्थितिकी के तराजू पर यह पूरी तरह निरर्थक है। अरुणाचल के संवेदनशील पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में जो एक लाख पेड़ कटेंगे, उससे वहां की स्थानीय जलवायु, वर्षा का चक्र, भूस्खलन की आवृत्ति और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसकी भरपाई देश के किसी अन्य कोने में पेड़ लगाकर कभी नहीं की जा सकती।

इस भारी प्राकृतिक कीमत को चुकाने के बाद यह जानना जरूरी है कि इस पूरे सौदे से अरुणाचल प्रदेश और उसके नागरिकों को अंततः क्या हासिल होने वाला है। सरकार के आर्थिक तथा रणनीतिक रोडमैप के अनुसार, यह परियोजना अरुणाचल को बिजली आधिक्य राज्य बनाने और उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके क्रियान्वयन से अरुणाचल प्रदेश को उत्पादित होने वाली कुल बिजली का 12 प्रतिशत हिस्सा रॉयल्टी के रूप में पूरी तरह मुफ्त मिलेगा, जिसे ग्रिड या अन्य राज्यों को बेचकर राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व अर्जित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, निर्माण और संचालन के चरणों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुदूरवर्ती और दुर्गम जिलों में पक्की सड़कों, पुलों, अस्पतालों और आधुनिक स्कूलों का विकास होगा, जो स्थानीय कनेक्टिविटी और जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका सामरिक सुरक्षा से जुड़ा है; चीन की सीमा के निकट होने के कारण इस नदी के निचले हिस्से पर भारत द्वारा इन बड़े बांधों का निर्माण करना बेहद जरूरी है, ताकि ऊपरी तटीय क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बांधों के जवाब में भारत अपने अंतरराष्ट्रीय जल अधिकारों को मजबूती से सुरक्षित कर सके।

निष्कर्ष के तौर पर यह स्पष्ट है कि 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को मंजूरी मिलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक नीतियों की एक बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन एक लाख पेड़ों की यह सामूहिक बलि इस जीत पर पर्यावरण की ओर से एक गहरा दाग भी है। जब हम एक लाख पेड़ काटते हैं, तो हम केवल लकड़ी का नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम हिमालय की संवेदनशील और दरकती पहाड़ियों की जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं, जिससे भविष्य में विनाशकारी भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और बड़े पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विकास और पर्यावरण के इस अंतहीन टकराव में अब हमें पुराने प्रशासनिक तौर-तरीकों से हटकर सोचने की सख्त जरूरत है। यदि इन पेड़ों को काटना एक अपरिहार्य तकनीकी मजबूरी है, तो इसके हर्जाने के तहत होने वाले वनीकरण को महज कागजी खानापूर्ति या दूसरे राज्यों में पेड़ लगाने की औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय सरकार और निर्माण कंपनियों को अरुणाचल के ही स्थानीय, भूस्खलन-संवेदनशील इलाकों में वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके युद्धस्तर पर सघन वनों को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाना होगा, क्योंकि विकास केवल तभी तक टिकाऊ और सार्थक है जब तक प्रकृति हमें खुलकर सांस लेने की अनुमति देती है।

बदलाव का जरिया बन सकेगी रामलीला मैदान की रैली

> सत्ता के खिलाफ विपक्षी दल जब भी रामलीला मैदान में रैली करते हैं, उनकी स्मृति में सात फरवरी 1977 की तारीख होती है। आपातकाल के बाद दिल्ली की उतरती ठंड के बीच जेपी के नाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण की अगुआई में हुई रैली में ही सत्ता परिवर्तन के बीज पड़े थे। इसे संयोग ही कहेंगे कि करीब आधी सदी बाद इसी रामलीला मैदान में आयोजित रैली के किरदार बदले हुए थे। 1977 में जिस रैली के निशाने पर कांग्रेस थी, करीब पांच दशक बाद की रैली में कांग्रेस बदली हुई भूमिका में रही।

उमेश चतुर्वेदी

इंदिरा के पोते राहुल गांधी की अगुआई में हुई 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली में निशाने पर वह भारतीय जनता पार्टी रही, जो तब जेपी की अगुआई में इंदिरा के खिलाफ खड़ी थी। यह बताने की जरूरत नहीं कि इसके कुछ ही दिनों बाद हुए आम चुनावों में सर्वशक्तिमान मानी जाने वाली इंदिरा गांधी की सत्ता का शिराजा बिखर गया था। ऐसे में सवाल यह उठना लाजमी है कि क्या राहुल की अगुआई वाली रामलीला मैदान की रैली देश की सत्ता को बदलने में कामयाब हो पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। केंद्रीय सत्ता पर नरेंद्र मोदी के काबिज होने के बाद विपक्षी दल बदलाव के प्रतीक माने जाने वाले रामलीला मैदान पर पांच और रैलियां आयोजित कर चुके हैं। हर रैली में मोदी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। लेकिन कुछ-एक राज्यों की सत्ता को छोड़ दें तो विपक्षी दलों की रैलियां 1977 की तरह कामयाब नहीं रहीं। हालांकि सरकार को अपने कुछ कदम जरूर पीछे खींचने पड़े। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था, जब 19 अप्रैल 2015 को कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने 'किसान-खेत मजदूर' रैली आयोजित की थी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 'भूमि अधिग्रहण अध्यादेश' के विरोध में आयोजित इस रैली के बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। कांग्रेस की ही अगुआई में विपक्षी दलों ने 14 दिसंबर 2019 को इसी रामलीला मैदान में 'भारत बचाओ' रैली की थी। जिसका मकसद, देश की आर्थिक स्थिति, गिरते जीडीपी, बेरोजगारी और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना रहा। इस रैली का असर यह हुआ कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्से महीनों तक आंदोलनरत रहे।

कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने रामलीला मैदान में चार सितंबर 2022 को 'महंगाई पर हल्ला बोल' रैली के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस रैली में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध किया गया। 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली में राहुल गांधी के भाषण की खूब चर्चा है। कुछ इसी तरह इस रैली में भी राहुल गांधी ने जो कहा था, उसे लेकर कई दिनों तक चर्चा और विमर्श जारी रहा। पिछले आम चुनाव के ठीक पहले 31 मार्च 2024 को फिर कांग्रेस ने विपक्षी दलों की 'लोकतंत्र बचाओ' महारैली आयोजित की। इस रैली का मकसद शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भूमि घोटाले में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करना रहा। इस रैली मोदी सरकार के विरोध में गठित विपक्षी



दलों के इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाना भी रहा। मोदी सरकार के गठन के बाद कांग्रेस की अगुआई में आयोजित हुई रामलीला मैदान की रैलियों के परिणामों पर नजर डालें तो देखेंगे कि 2024 की रैली के अलावा किसी दूसरी रैली का मोदी सरकार की सेहत पर खास असर नहीं दिखा। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का बहुमत के आंकड़े से दूर होने के पीछे इस रैली के असर को देखा-समझा जा सकता है। फिर भी कहा जा सकता है कि इस रैली ने मोदी के अजेयता के मिथ को चोट जरूर पहुंचाई। यह बात और है कि इससे बीजेपी निराश नहीं हुई। अगर वह निराश हुई होती तो वह बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के चुनाव नहीं जीत सकती थी। विपक्ष चाहे लाख दावा करे कि इन राज्यों में एसआईआर के बहाने वोटों की चोरी हुई, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी की अगुआई में बीजेपी निराशा झाड़कर उठ खड़ी होती रही और चुनाव-दर-चुनाव सफलताएं हासिल करती रही।राहुल गांधी के निशाने पर इन दिनों चार लोग हैं और अपने हर भाषण और प्रेस कांफ्रेंस में वह अशोभन ढंग से इन नामों पर हमला करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर राहुल टिप्पणियां कर रहे हैं। रामलीला मैदान में भी उन्होंने अशोभन तरीके से नाम लिए, लेकिन लगे हाथों यह कहने से भी नहीं चूके कि वे किसी से नफरत नहीं करते। राहुल का यह रूप दिलचस्प ही कहा जाएगा कि नफरत नहीं भी करते, लेकिन उनके शब्दों में नकारात्मकता ठीक से झलकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानें या न मानें, लेकिन अमर्यादित तरीके से निशाना बनाने के चलते राहुल के शब्दों को आम जन गंभीरता से नहीं ले पाता। लोकसभा के चुनाव में अभी दो साल का वक्त है, लेकिन अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर राज्य में कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है। पंजाब में उसका मुकाबला विपक्षी खेमे के ही आम आदमी पार्टी से है। यहां उसके लिए कशमकश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू है। हालांकि वह कोशिश कर रही है कि पिछलग्गू का ठप्पा उसके दामन से साफ हो सके। बाकी तीन राज्यों में वह बीजेपी के बरक्स मुकाबले में है। रामलीला मैदान की रैली का घोषित उद्देश्य भले ही मोदी, शाह, और भागवत का विरोध एवं ज्ञानेश का इस्तीफा लेना हो। लेकिन अघोषित मकसद इन राज्यों के चुनावी समर में बीजेपी को मात देना है। इस दिशा में अभी से माहौल बनाना है। मोदी के उभार के बाद रामलीला मैदान में आयोजित अतीत की रैलियों और एक नवंबर की रैली में एक अंतर साफ दिखता है। पहले ममता समेत कुछ विपक्षी दल राहुल को नेता मानने से कतराते थे। लेकिन इस रैली में एक तरह से राहुल की अगुआई स्वीकार कर ली गई है। राहुल निर्विवाद तौर पर विपक्षी खेमे के नेता के तौर पर उभरे हैं। विपक्षी खेमे में राहुल की यह स्वीकारोक्ति बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकती है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच मजेदार होंगे: रायन

ऑकलैंड । भारत के फॉरवर्ड रायन विलियम्स न्यूजीलैंड में खेलने के अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल भारतीय पुरुषों के देश के पहले दौरे की तैयारी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल टीम गुरुवार को ऑकलैंड के गो मीडिया स्टेडियम में दो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचों में से पहले मैच में ऑल व्हाइट्स का सामना करने के लिए तैयार है। यह दोनों टीमों के बीच तीसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। इससे पहले 1981 और 2018 में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं।



यह दौरा भारतीय टीम के ज्यादातर सदस्यों के लिए नया है। विलियम्स ऑस्ट्रेलियाई क्लब पर्थ ग्लोरी के साथ अपने समय के दौरान न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं। 33 साल के इस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में पामर्स्टन नॉर्थ में वेलिंगटन फीनिक्स के खिलाफ ग्लोरी के 2-2 से ड्रॉ मैच में हिस्सा लिया था, जिसे 'डिस्टेंस डर्बी' के नाम से जाना जाता है। तस्मान में यात्रा करने की जरूरतों का अनुभव होने के कारण, वह लंबी यात्रा और समय के अंतर से आने वाली चुनौतियों को जानते हैं।

विलियम्स ने कहा, 'हर बार जब मैं खेलने के लिए न्यूजीलैंड आया हूं, तो यह हमेशा मुश्किल रहा है क्योंकि यह हर चीज से बहुत दूर है। पर्थ से, यह बहुत दूर है। समय का अंतर भी एक ऐसी चीज है जिसे आपको मैनेज करना होता है।' ऑकलैंड भारत से साढ़े सात घंटे आगे है, इसलिए बॉडी क्लॉक में बदलाव को मैनेज करना टीम की पहली प्राथमिकताओं में से एक था।

विलियम्स ने कहा कि उन्होंने यात्रा के दौरान एक प्लान्ड स्लीप रूटीन का पालन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच यात्रा करने के कई सालों के अनुभव का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, 'मेरा प्लान फ्लाइट के पहले हिस्से में सोने का था, जो मलेशिया के लिए था। मैं कुछ घंटे सोया, फिर जब तक हम यहां नहीं पहुंच गए, तब तक लगभग सोया ही नहीं। यह आपकी पूरी बॉडी क्लॉक को एक तरह से रीसेट कर देता है, इसलिए आप यहां आ सकते हैं, सीधे सो सकते हैं और पूरी रात सोने की कोशिश कर सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम में नंदिनी शर्मा का चयन



चंडीगढ़ । चंडीगढ़ की तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा को दिसंबर में होने वाले भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम इस दौरे पर एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। दौरे की शुरुआत 9 दिसंबर को गेकेबरहा में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद तीन वनडे मुकाबले पार्ल, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन में खेले जाएंगे। दौरे का समापन बेनोनी और पोटचेफस्ट्रूम में होने वाली तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के साथ होगा। इस साल की शुरुआत में भी नंदिनी शर्मा ने इतिहास रचा था। वह यूटी क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) की पहली खिलाड़ी बनी थीं, जिन्हें ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली थी। हालांकि, उन्हें अभी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है। नंदिनी के चयन पर यूटीसीए के अध्यक्ष सारांश टंडन ने कहा की दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट और वनडे दोनों टीमों में नंदिनी का चयन चंडीगढ़ और यूटीसीए के लिए बेहद गर्व की बात है। घरेलू क्रिकेट से लॉर्ड्स तक का सफर और अब ऑल-फॉर्मेट विदेशी दौरे के लिए भारतीय टीम में चयन उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार शानदार प्रदर्शन का परिणाम है। हमें पूरा विश्वास है कि नंदिनी आगे भी चंडीगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगी।

हार्दिक को विदाई और अर्शदीप का स्वागत



मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट

मुंबई । मुंबई आईपीएल 2024 से आईपीएल 2026 तक मुंबई इंडियंस (एमआई) के कप्तान रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाता अब इस टीम से टूट चुका है। एमआई ने सोशल मीडिया पर हार्दिक को उनके आगे के सफर के लिए शुभकामना भी दे दिया है। साथ ही एमआई ने अपने साथ जुड़े अर्शदीप सिंह का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एमआई ने कई पोस्ट साझा करते हुए अपने कप्तान हार्दिक को बधाई दी है। एमआई ने अपने सबसे पहली पोस्ट में लिखा, 'हार्दिक, ब्लू एंड गोल्ड को जोश और गर्व के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए धन्यवाद। हम आपको आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं।'

एक अन्य पोस्ट में हार्दिक की प्रशंसा में एमआई ने लिखा, 'उतार-चढ़ाव के बीच, मुंबई इंडियंस की कहानी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, हार्दिक।' हार्दिक पंड्या आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। वह ट्रेड डील के तहत 18 करोड़ में पंजाब से जुड़े हैं। 2019 से पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं।

एमआई ने पंजाब किंग्स से हार्दिक के बदले अर्शदीप सिंह को अपने साथ जोड़ा है। अर्शदीप भी 18 करोड़ में एमआई से जुड़ें हैं। एमआई ने सोशल मीडिया पर अर्शदीप सिंह की एक छोटी वीडियो साझा करते हुए टीम में उनका स्वागत किया है। एक अन्य पोस्ट में एमआई ने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की फोटो साझा करते हुए लिखा है, 'प्रिय बल्लेबाजों, स्टंप उड़ेंगे, किनारे उड़ेंगे। उंगलियां ऊपर जाएंगी। और वो पैर की उंगलियां? बेहतर होगा कि उन्हें बचाकर रखें। यह कॉम्बो जल्द ही जोड़ों में शिकार करेगा, सिर्फ टी20 आई में ही नहीं बल्कि आईपीएल में भी।'

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करती है और दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी जोड़ी मानी जाती है। इन दोनों को साथ पाकर मुंबई इंडियंस बेहद खुश है। पंजाब किंग्स ने भी एक्स पर अर्शदीप सिंह के टीम से अलग होने की जानकारी देते हुए लिखा, 'एक युवा शेर से एक ऐसा नाम जिसने पंजाब को गर्व महसूस कराया। अर्शदीप, यहां हमेशा आपका घर रहेगा।'

हार्दिक का आना आईपीएल खिताब की तरफ एक जरूरी कदम : पंजाब किंग्स सीईओ सतीश मेनन

नई दिल्ली । नई दिल्ली पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के सीईओ सतीश मेनन ने बुधवार को प्रीमियर सीम-बॉलिंग ऑल-राउंडर हार्दिक पांड्या को साइन करने को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टाइटल जीतने की फ्रेंचाइजी की कोशिश में एक जरूरी कदम बताया।



बीसीसीआई ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि पंड्या मुंबई इंडियंस (एमआई) से एक ट्रेड डील में पंजाब किंग्स में शामिल हुए। डील के तहत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए। ट्रेड प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह से चल रही थी। पंजाब किंग्स अभी तक कोई आईपीएल खिताब नहीं जीता है। उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 और 2025 में रहा है, जब टीम फाइनल में पहुंची थी।

मेनन ने बुधवार को एक बयान में कहा, 'हमें हार्दिक का पंजाब किंग्स परिवार में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। वह एक साबित मैच-विनर है, जो जबरदस्त अनुभव, आत्मविश्वास और जीतने की सोच लेकर आए है। बैट और बॉल दोनों से गेम का रुख बदलने की उनकी काबिलियत उन्हें हमारी टीम के लिए एक कीमती बनाती है। हम आईपीएल के 20वें सीजन में कदम रख रहे हैं, हमारा फोकस एक ऐसी टीम बनाने पर है जो सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला कर सके और ट्रॉफी पंजाब घर ला सके। हार्दिक का आना उस दिशा में एक जरूरी कदम है।'

मेनन ने अर्शदीप के पंजाब किंग्स से मुंबई इंडिया का हिस्सा बनने पर कहा, 'अर्शदीप कई सालों से पंजाब किंग्स का अहम हिस्सा रहे हैं, और यह हमारे लिए भी एक भावुक पल है। हमने उन्हें देश के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक बनते देखा है, और हमें उनके सफर पर बहुत गर्व है।

उन्होंने मैदान पर और मैदान के बाहर, दोनों जगह फ्रेंचाइजी के लिए बहुत योगदान दिया है, और पंजाब किंग्स परिवार में हमेशा एक खास जगह रखेंगे। हम उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं और उनकी लगातार सफलता की कामना करते हैं।'

डब्ल्यूटीए फाइनल्स

नोस्कोवा ने गॉफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई



इंडियन वेल्स लिंडा नोस्कोवा ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नोस्कोवा ने कोको गॉफ को 75 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-3 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। नोस्कोवा 2011 में पेट्रा क्वितोवा के बाद अपने पहले डब्ल्यूटीए फाइनल्स में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। डब्ल्यूटीए के आंकड़ों के अनुसार, वह 2024 में गॉफ के बाद अपने पहले दो राउंड-रॉबिन मैच जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी हैं और 2021 में एनेट कोंटावेइट के बाद ऐसा करने वाली पहली नंबर 8 सीड हैं। लिंडा नोस्कोवा ने पत्रकारों से कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं सेमीफाइनल में हूं।

मैच खत्म होने के ठीक बाद, मैं पहले से ही इस बात पर फोकस कर रही थी कि मैं दो दिन में जेसी (पेगुला) के साथ कैसे खेलूंगी। इसलिए मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं बदला है। मैं अभी भी जीतना चाहती हूं। मैं अभी भी जो भी स्कोर, जो भी जीत मुमकिन हो, हासिल करना चाहती हूं। मैं यहां असल में मैच नहीं खेल रही हूं, इसलिए यह कुछ अलग नहीं होने वाला है।

नोस्कोवा ने गॉफ को पांच बार ब्रेक किया, जिसमें शुरुआती सेट में चार बार शामिल हैं। उसने नौ में से पांच ब्रेक-पॉइंट मौकों को कन्वर्ट किया और गॉफ की दूसरी सर्व पर 75 प्रतिशत (24 में से 18) पॉइंट जीते। रिटर्न पर नोस्कोवा ने जो दबाव डाला, उससे उन्हें दोनों सेट में 4-1 की लीड बनाने में मदद मिली। यह नोस्कोवा के लिए इस सीजन की छठी टॉप-10 जीत है, जिसने जुलाई में विंबलडन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था।

गॉफ अपने तीसरे राउंड-रॉबिन मैच में मार्टा कोस्त्युक का सामना करेंगी। उन्हें सेमीफाइनल में आगे बढ़ने के लिए एक जीत की जरूरत है। गॉफ, जो 2006 में मारिया शारापोवा के बाद डब्ल्यूटीए फाइनल्स में अपने तीसरे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनना चाहती हैं, ने छह में से चार हेड-टू-हेड मुकाबले जीते हैं। हालांकि, जेसिका पेगुला, कोस्त्युक पर एक घंटे और 29 मिनट में 6-2, 7-5 से जीत के साथ टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आगे बढ़ने की दौड़ में बनी हुई हैं।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग

रहमत शाह ने रचा इतिहास, टॉप-10 में जगह बनाने वाले पहले अफगान खिलाड़ी बने

दुबई। दुबई अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह ने इतिहास रच दिया है। वे आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाले देश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के बाद वे सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। वह टेस्ट क्रिकेट की किसी भी श्रेणी में टॉप-10 में जगह बनाने वाले पहले अफगान क्रिकेटर बन गए हैं। दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में



173 रन बनाने के बाद रहमत छह पायदान ऊपर चढ़े, जिससे उन्हें करियर की सबसे अच्छी रेटिंग मिली और वे भारत के कप्तान शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम और श्रीलंका के कामिंदू मेंडिस जैसे बल्लेबाजों से आगे निकल गए। 33 साल के रहमत की यह पारी टेस्ट क्रिकेट में उनकी पांचवीं सेंचुरी और इस साल की दूसरी सेंचुरी थी। इस महीने की शुरुआत में, टीम आईसीसी मेन्स वनडे टीम रैंकिंग में अपनी अब तक की सबसे ऊंची जगह (छठे नंबर) पर पहुंच गई।

बांग्लादेश महिला टीम की फिटनेस और अनुशासन पर पूर्व हेड कोच

सरोवर इमरान ने सवाल उठाए

नई दिल्ली। बांग्लादेश महिला टीम के पूर्व हेड कोच सरोवर इमरान ने टीम के फिटनेस स्तर और ट्रेनिंग कल्चर पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि खिलाड़ियों को उनके कम्फर्ट जोन से बाहर निकालने और ज्यादा अनुशासन लाने की उनकी कोशिशों की वजह से उन्हें अपनी भूमिका से अलग होना पड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने एशियन गेम्स के बाद अक्टूबर में सरोवर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने दिया और बाद में उनकी जगह डेविड हेम्प को नियुक्त किया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बीसीबी से सरोवर इमरान की शिकायत की थी और उनके तरीकों पर सवाल उठाया था। सरोवर ने पहले बांग्लादेश के एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद ड्रेसिंग रूम में अशांति की बात कही थी, जिसके बाद बोर्ड ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार किया। प्रस्तावित कार्रवाई को आखिरकार वापस ले लिया गया, जिसमें बीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट के साथ उनके लंबे जुड़ाव को ध्यान में रखा।

सरोवर ने कहा कि बोर्ड ने उन्हें जारी रखने का फैसला करने से पहले कभी उनसे सफाई नहीं मांगी। उन्होंने कहा, एशियन गेम्स और एशिया कप के बाद बीसीबी ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। मुझे एक पत्र मिला कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि कोई दूसरा कोच जाएगा। बीसीबी के साथ मेरी बस इतनी ही बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कोचिंग का माहौल बहुत ज्यादा संतुलन बनाने वाला हो गया था, जिससे सुधार की बहुत कम गुंजाइश बची थी।

महिला टीम में शामिल होने के बाद अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, जहां तक ??मेरे गुस्से की बात है, जब मैं महिला टीम में आया, तो मैंने देखा कि गेंदबाजी कोच से लेकर स्पिन बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, ट्रेनर और फिजियो सभी बहुत शांत थे। वे महिला क्रिकेटरों की हर बात सुनते हैं और इस कम्फर्ट जोन में रहकर वे सुधार नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारी टीम आज भी वैसी ही है जैसी पांच साल पहले थी।



इमरान ने कहा, एक स्पिनर 30 गेंदें फेंकने के बाद कोच से कहती है कि वह अब और गेंदबाजी नहीं करेगी और कोच मान जाता है। एक या दो बल्लेबाज पूरे दिन बल्लेबाजी करते हैं। यह सब देखने के बाद मैंने दखल देना शुरू कर दिया। मैंने उनकी फिटनेस को लेकर भी दखल दिया।

उन्होंने कहा, जब मुझे उन्हें डांटने की जरूरत थी तो मैंने वैसा ही किया और अगर आप कहते हैं कि यह गुस्सा है तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट सुधर सकता है। मुझे लगा कि मैं उन्हें सुधार सकता हूं और मैंने सात से आठ टूर किए और सब कुछ सिर्फ एक या दो टूर में फेल होने की वजह से खत्म हो गया।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए न्यायाधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यालय नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेलः alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013)66670